

01-15 दिसंबर

न्यू इंडिया

समाचार



सहकारिता से प्रशस्त विकसित भारत का मार्ग

सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ
सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल
भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन
बना, अब 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने
की ओर अग्रसर भारत...



ई-कॉपी के लिए **QR** स्कैन करें

बिहार विधानसभा चुनाव- 2025

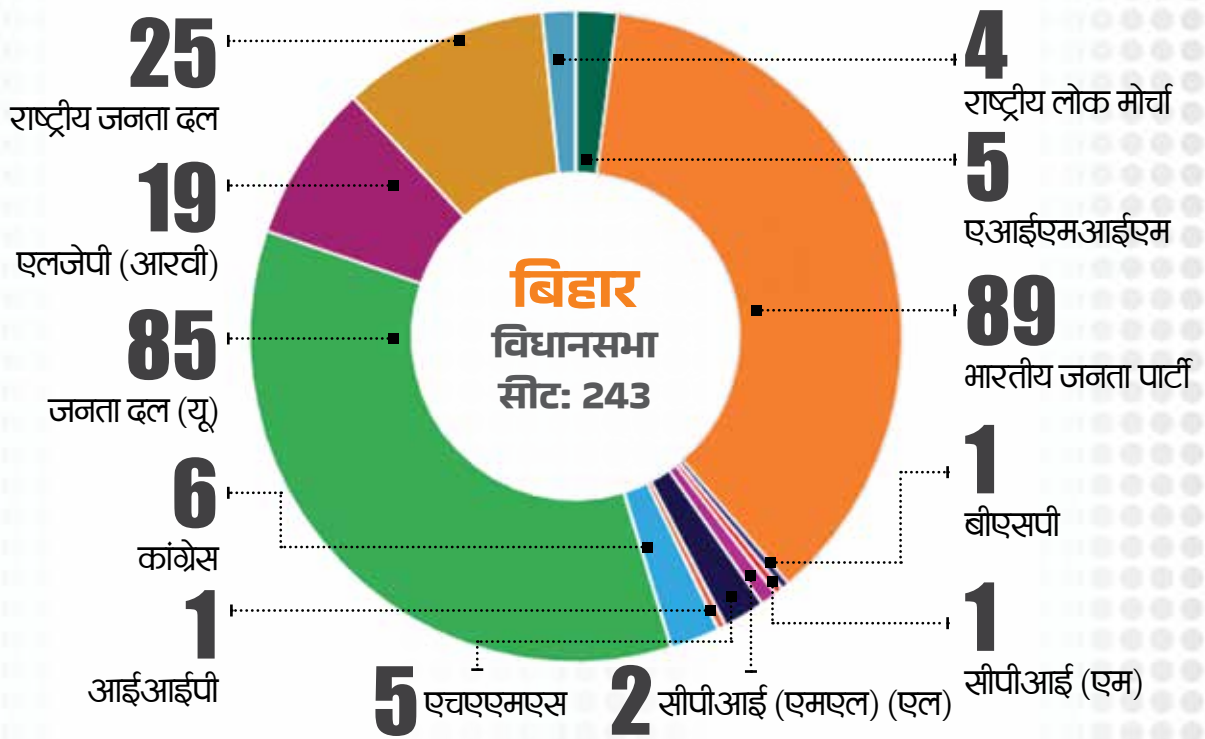
परिणाम पर एक नजर

बिहार वो धरती है, जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी होने का गौरव दिया। बिहार विधानसभा चुनाव-2025 में अब तक के रिकॉर्ड मतदान ने सिद्ध किया है कि भारत अब सच्चे सामाजिक न्याय के लिए वोट कर रहा है, जहां हर परिवार को समानता, सम्मान और अवसर मिलता है। लोकतंत्र के इस उत्सव का संदेश है कि भारत के लोग अब केवल विकास चाहते हैं, तेज विकास चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं...

रिकॉर्ड बना

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें मतदान प्रतिशत **67.13** रहा, जो 1951 के बाद से सबसे अधिक है।

1951 के बाद से बिहार में **71.78%** मतदान के साथ महिला मतदाताओं की रही अब तक की सबसे अधिक भागीदारी।



स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग

मैं आज देश और दुनियाभर के निवेशकों से भी कहूंगा कि बिहार आपके स्वागत के लिए तैयार है। मैं देश और दुनिया में बसी बिहार की संतानों से भी कहूंगा, ये बिहार में निवेश करने का सबसे उपयुक्त समय है। साथियों, आज मैं बिहार की एक-एक मां, एक-एक युवा, एक-एक किसान, एक-एक गरीब परिवार को कहना चाहता हूँ... आपका भरोसा, ये मेरा प्रण है। आपकी आशा, मेरा संकल्प है। मेरे नौजवान साथियों, आपकी आकांक्षा, ये मेरी प्रेरणा है। हम मिलकर एक ऐसा बिहार बनाएंगे, जो समृद्ध होगा, विकसित होगा।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधान संपादक

धीरेन्द्र ओझा

प्रधान महानिदेशक

पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक

संतोष कुमार

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक

पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक

अखिलेश कुमार

चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन

सुमित कुमार (अंग्रेजी)

रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी)

नदीम अहमद (उर्दू)

सीनियर डिजाइनर

फूलचंद तिवारी

डिजाइनर

अभय गुप्ता

सत्यम सिंह



13 भाषाओं में उपलब्ध
न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने
के लिए क्लिक करें।

<https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx>

न्यू इंडिया समाचार के पुराने
अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

<https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx>



न्यू इंडिया समाचार के बारे में
लगातार अपडेट के लिए फॉलो
करें: @NISPIBIndia

सहकारिता समृद्ध समाज की सशक्त नींव



छोटी-छोटी वस्तुएं, थोड़े-थोड़े संसाधन भी जब साथ जोड़ दिए जाते हैं, तो उनसे बड़े-बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में कही गई यह बात भारत की प्राचीन व्यवस्था-सहकारिता के लिए बेहद सटीक है। सहकारिता के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने बीते कुछ वर्षों में आमूल-चूल परिवर्तन कर नई ऊर्जा का संचार किया है। अब सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन बनकर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को कर रहा है साकार...

| 12-31



वंदे मातरम के 150 वर्ष का स्मरणोत्सव

वंदे मातरम... आजादी के परवानों का तराना



वंदे मातरम के 150वें वर्ष में
साल भर चलने वाले स्मरणोत्सव
का शुभारंभ | 10-11

समाचार सार

| 4-5

व्यक्तित्व : नंदलाल बोस

जिन्होंने संविधान के पन्नों पर उकेरी भारत की पहचान

| 6-7

आदिवासी कल्याण केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर पीएम मोदी का संबोधन

| 32-33

अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस - 3 दिसंबर

भारत में दिव्यांगजनों का बढ़ता आत्मविश्वास

| 34-35

नाल्सा का 20वां राष्ट्रीय सम्मेलन

न्याय की हर व्यक्ति तक पहुंच ही सामाजिक न्याय की नींव

| 36-37

4 नई वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

अब देश में 164 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन

| 38-39

‘देवभूमि उत्तराखंड’ भारत के आध्यत्मिक जीवन की धड़कन

उत्तराखंड की रजत जयंती पर पीएम मोदी का संबोधन

| 40-41

हर तरह की आपदा में सुरक्षित न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट

परमाणु ऊर्जा पर विशेष रिपोर्ट

| 42-43

नए भारत की खेल भावना का प्रतीक

आईसीसी महिला विश्व कप चैंपियन से पीएम मोदी की बातचीत

| 44-45

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय

निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी... आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा

| 48



सीमा से ही नहीं, संस्कृति से भी हैं जुड़े
भारत-भूटान

पीएम मोदी की दो दिवसीय भूटान की यात्रा | 46-47

आतंकवाद पर दो-टूक

षडयंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा...



आतंकवाद के विरुद्ध पीएम
मोदी का सख्त संदेश | 8-9

संपादक की कलम से...

सहकारिता से भारत के भविष्य को मिल रहा नया आकार

सादर नमस्कार।

भारत में सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक विकास को बढ़ावा देने में सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सहकारिता देश के कमजोर और पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण का, उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने का, उनके सामाजिक तथा वित्तीय समावेशन का एक अत्यंत सशक्त माध्यम रही है।

देश में सहकारिता की एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है, जो आजादी से पहले आर्थिक आंदोलन का अहम हिस्सा थी। साल 2021 में जब सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई, तो इसकी परंपरा को नई ऊर्जा और ताकत मिली। आज, भारत में 8.44 लाख से भी अधिक सहकारी समितियां हैं और 30 करोड़ से अधिक सदस्य इससे जुड़े हैं। अब देश सहकारी तंत्र का विस्तार कर एक नया आर्थिक मॉडल बनाने के रास्ते पर चल पड़ा है, जो पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य और देश के विकास के संकल्प को पूरा करने में काफी मददगार साबित होगा।

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के साढ़े चार वर्ष में 100 से अधिक प्रशासनिक और नीतिगत पहल के साथ इस क्षेत्र को नई ऊर्जा मिली है। पांच पी यानी पीपुल, प्लेटफॉर्म, पैक्स, पॉलिसी और प्रोस्पेक्टिविटी पर आधारित इस पहल ने भारत के सहकारिता आंदोलन को विस्तार और नई मजबूती दी है। सहकार से समृद्धि के मंत्र पर अग्रसर सहकारिता क्षेत्र भारत के भविष्य को नया आकार दे रहा है। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया और हाल ही में अमूल एवं इफको ने दुनिया की शीर्ष 10 सहकारी संस्थाओं में पहला तथा दूसरा स्थान हासिल किया है। वर्ष 1946 में 14 दिसंबर के दिन ही अमूल के नाम से मशहूर सहकारी संस्था का पंजीकरण भी हुआ था। इसी संदर्भ में सहकार से समृद्धि इस बार के हमारे अंक की आवरण कथा बनी है।

इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में भारतीय कला के नायक नंदलाल बोस, आईसीसी महिला विश्व कप चैंपियन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत, दिल्ली बम विस्फोट पर पीएम मोदी की दो-टूक के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और परमाणु ऊर्जा पर विशेष सामग्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है।

साथ ही, पत्रिका के इनसाइड पेज पर बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम और बैंक कवर पर 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर विशेष सामग्री को समाहित किया गया है।

आप अपना सुझाव हमें भेजते रहें।

(धीरेन्द्र ओझा)



हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।

<https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx>

आपकी बात...



बहुमूल्य जानकारी के साथ मिलता है उचित मार्गदर्शन

मुझे हमेशा पाक्षिक पत्रिका 'न्यू इंडिया समाचार' का इंतजार रहता है। यह पत्रिका बेहतर तरीके से डिजाइन की जाती है। इसमें दी गई सामग्री के माध्यम से मुझे बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों से मैं अवगत होता हूँ। यह पत्रिका अपने देश से जोड़ती है, ऊर्जा प्रदान करने के साथ- साथ उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करती है।

Panditaarun@gmail.com

विकास की गति का सही आकलन करने में मददगार

न्यू इंडिया समाचार एक बेहतरीन पत्रिका है। इसका नवीनतम अंक महत्वपूर्ण जानकारियों से भरपूर है। कवर स्टोरी शानदार है। साथ ही अन्य सामग्री भी ज्ञानवर्धक है। इस पत्रिका के आंकड़े और तथ्य बिल्कुल सटीक जानकारी प्रदान करते हैं जो कि विकास की गति का सही आकलन करने में मददगार है।

anjuranip79@gmail.com

सरकारी नीतियों को समझने का एक बेहतरीन माध्यम

हाल ही में मुझे न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ने का अवसर मिला। यह पत्रिका कई दृष्टिकोण से अद्वितीय है। सरकारी नीतियों को समझने का यह एक बेहतरीन माध्यम है। इसमें नई नीतियों, सामाजिक मुद्दों, विकास और सरकार द्वारा की गई कई अन्य पहलों के बारे में उपयोगी एवं तथ्यपरक जानकारी पढ़ने को मिलती है।

amit.tiwari9911@gmail.com

पत्रिका के हर अंक से कुछ नया सीखने को है मिलता

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका के माध्यम से मैं देश-विदेश में होने वाली सभी घटनाओं से अवगत होता हूँ। हर अंक से कुछ नया सीखने को मिलता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए न्यू इंडिया समाचार पत्रिका की खबरें उपयोगी है। इसकी त्रुटिहीन सामग्री और अंतर्दृष्टि ने मुझे सम-सामयिकी विषयों की व्यापक समझ विकसित करने में मदद की।

dinesh_dubey1977@rediffmail.com

देश के विकास के बारे में मिलती है बहुत सारी जानकारी

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ना और देश की प्रगति के बारे में निरंतर जानना सुखद होता है। यह एक बहुत ही ज्ञानवर्धक पत्रिका है। इसमें देश के विकास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसे आकर्षक शैली में छापा जाता है। इसका डिजाइन भी बहुत बेहतरीन रहता है।

purshottam.79fzd@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-1077,
सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003.
ईमेल- response-nis@pib.gov.in



न्यू इंडिया समाचार को आकाशवाणी के
एफएम गोल्ड पर हर शनिवार - रविवार
को दोपहर 3:10 से 3:25 बजे तक सुनने
के लिए QR कोड स्कैन करें।



समाचार सार

क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि

क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या में 1,125% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है।

इस सूची में वर्ष 2016 में जहां देश भर के 24 विश्वविद्यालय शामिल थे वहीं 2026 की रैंकिंग के अनुसार

इसकी संख्या बढ़ कर 294 हो गई है। सूची के मुताबिक, एशिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में 5

जबकि शीर्ष 50 में 28 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। भारत अब एशिया का "रिसर्व

पावरहाउस" बन रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आधुनिक शिक्षा, शोध

एवं नवाचार से भारतीय विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर नई पहचान बना रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में

भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या में हुई रिकॉर्ड वृद्धि पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने

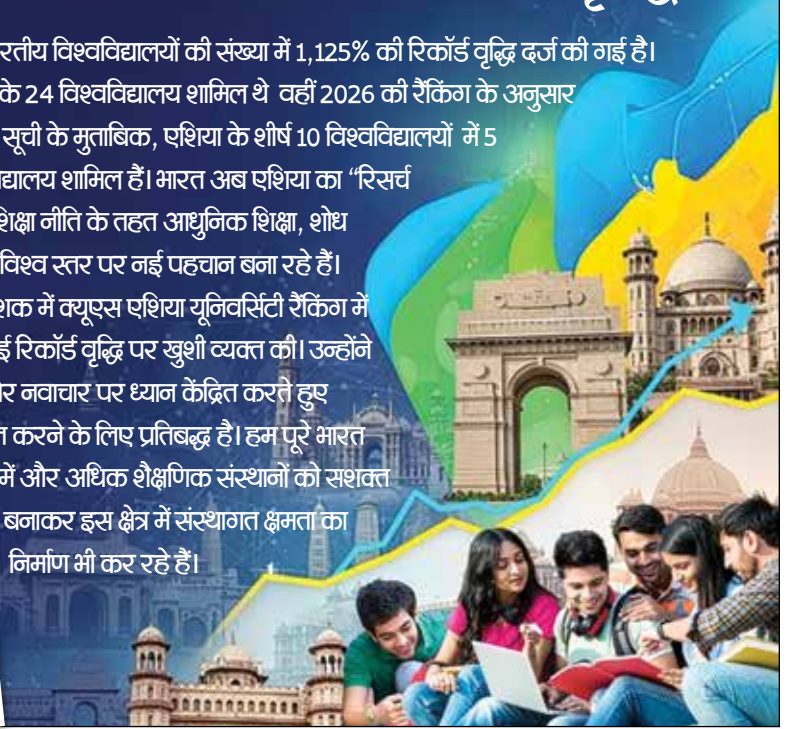
कहा कि हमारी सरकार अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए

युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम पूरे भारत

में और अधिक शैक्षणिक संस्थानों को सशक्त

बनाकर इस क्षेत्र में संस्थागत क्षमता का

निर्माण भी कर रहे हैं।



गोल्ड पर निशाना साध सम्राट राणा ने रचा इतिहास



भारत के सम्राट राणा ने काहिरा में

आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व

चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर

पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत कर

इतिहास रच दिया है। इस जीत के साथ

राणा व्यक्तिगत एयर पिस्टल

विश्व खिताब जीतने वाले

पहले भारतीय बन गए

हैं। राणा ने 243.7 अंकों

के साथ पुरुषों की 10

मीटर एयर पिस्टल

स्पर्धा का स्वर्ण पदक

जीता जबकि भारत के

ही वरुण तोमर को कांस्य

पदक मिला।

बिहार की गोगाबिल झील को मिला रामसर साइट का दर्जा

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत ने एक और बड़ी

उपलब्धि हासिल की है। देश की एक आर्द्रभूमि, बिहार

की गोगाबिल झील को रामसर साइट का दर्जा दिया

गया है। 86.63 हेक्टेयर में फैली यह झील बिहार के

कटिहार जिले में है। इस उपलब्धि के साथ ही, अब

बिहार, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान

पर जबकि भारत एशिया में पहले एवं विश्व में तीसरे

स्थान पर पहुंच गया है। देश में अब रामसर स्थलों की

संख्या बढ़ कर 94 हो गई है, इसमें से 67 नए स्थल

पिछले 11 वर्षों में जोड़े गए हैं।



कबाड़ बिक्री से अर्जित किए गए करीब 4,100 करोड़ रुपये

विशेष स्वच्छता अभियान के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों से कबाड़ के निपटान के जरिए विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 तक 4,085 करोड़ से अधिक रुपये अर्जित किए गए हैं। सरकारी कार्यालयों से कबाड़ हटा कर स्वच्छता का यह अभियान वर्ष 2021 से चलाया जा रहा है जिसमें अभी तक यह राशि इकट्ठा की गई है। केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के मुताबिक, कबाड़ बेचकर जो राशि अर्जित की गई है वह एक मेगा अंतरिक्ष मिशन या कई चंद्रयान अंतरिक्ष मिशन के कुल बजट के बराबर है। विशेष स्वच्छता अभियान का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी रहा कि 231.75 लाख वर्गफुट जगह उपयोग के लिए खाली हो गई जो पहले अपशिष्ट पदार्थों, पुराने फर्नीचर, कबाड़ से भरी हुई थी। इस अभियान से इतनी जगह खाली हुई है कि आर्थिक गतिविधियों के लिए एक विशाल मॉल या कोई अन्य विशाल स्ट्रक्चर बनाने के लिए पर्याप्त है।



यूनेस्को ने लखनऊ को दिया 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' का सम्मान

दुनिया भर में अपनी अनूठी कलाओं और संस्कृतियों के लिए प्रसिद्ध लखनऊ को यूनेस्को ने 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' का सम्मान दिया है। यह भारत की कालातीत परंपराएं, संस्कृति और मूल्यों को वैश्विक मंच पर अभूतपूर्व मान्यता और सम्मान को दर्शाता है। यह सम्मान शहर की विशिष्ट पाक विरासत और समृद्ध परंपराओं में असाधारण योगदान का प्रतीक है। इस सम्मान ने लखनऊ की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। अब यहां का स्वाद दुनिया भर में पहुंचेगा। लखनऊ को यूनेस्को द्वारा 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' घोषित किये जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लखनऊ, एक जीवंत संस्कृति का पर्याय है जिसके मूल में शानदार पाक-कला संस्कृति है। मुझे खुशी है कि यूनेस्को ने लखनऊ के इस पहलू को मान्यता दी है। मैं दुनिया भर के लोगों से लखनऊ आने और इसकी विशिष्टता को अनुभव करने का आह्वान करता हूं।



दोगुनी होगी 'अमृत फार्मसी'

सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2015 में शुरू की गई 'अमृत फार्मसी' ने पिछले 10 वर्ष में करोड़ों मरीजों को 50 से 90% तक सस्ती दवा और प्रत्यारोपण (इंप्लांट) उपलब्ध कराई है। देश भर में अभी तक 255 अमृत फार्मसी है जिसे बढ़ा कर निकट भविष्य में अब 500 करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक अमृत फार्मसी से 6.85 करोड़ से अधिक रोगियों को लाभ मिला है। इन मरीजों को इसके माध्यम से अब तक 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की दवाएं वितरित की जा चुकी हैं, जिससे उनकी लगभग 8,400 करोड़ रुपये की बचत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हर चिकित्सा महाविद्यालय और हर जिला अस्पताल में अमृत फार्मसी हो ताकि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के हर स्तर पर नागरिकों को किफायती दवा मिले।



जिन्होंने संविधान के पन्नों पर उकेरी भारत की पहचान

आधुनिक भारतीय कला के जनक माने जाने वाले राष्ट्रवादी चित्रकार नंदलाल बोस ने भारतीय चित्रकला को शिखर तक पहुंचाया। कूची के जादूगर जिन्होंने संविधान के पन्नों में उकेरी भारत की पहचान और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों- भारत रत्न और पद्मश्री प्रतीकों के भी बनाए स्केच, ऐसे नंदलाल बोस की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन...



जन्म : 3 दिसंबर 1882, मृत्यु : 16 अप्रैल 1966

आधुनिक भारतीय कला के प्रणेता और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मशहूर कलाकार नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान के मूल हस्तलिखित पन्नों को भारतीय पहचान से समृद्ध किया। 221 पन्नों के इस दस्तावेज के सभी पन्नों पर चित्र बनाना संभव नहीं था। ऐसे में उन्होंने संविधान के हर भाग की शुरुआत में 8x13 इंच के चित्र बनाए। संविधान में कुल 22 भाग हैं। इस तरह उन्हें भारतीय संविधान की इस मूल प्रति को अपने 22 चित्रों से सजाने का मौका मिला। इन 22 चित्रों को बनाने में चार साल लगे। उनका काम न केवल संविधान की ऐतिहासिकता को जीवित रखता है बल्कि यह हमें भारतीय संस्कृति, समृद्ध इतिहास, धर्म, परंपरा, उच्च मानव मूल्यों और एकता का अहसास भी कराता है।

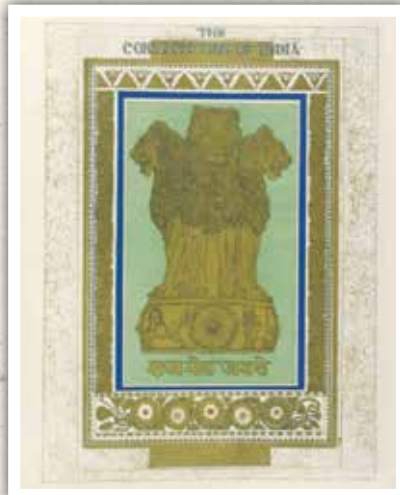
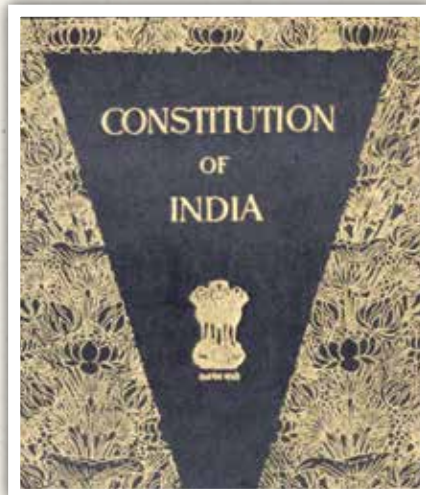
संविधान में भगवान राम, बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, गुरुकुल, भगवतगीता के संदेश, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, नालंदा विश्वविद्यालय, नटराज का भी चित्र मिलता है। इन चित्रों के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने का काम किया। इनके प्रसिद्ध चित्रों में 'डांडी मार्च', 'संथाली कन्या', 'सती का देह त्याग' शामिल है। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान उन्होंने गांधी जी के सफेद लिनोकट प्रिंट पर काली आकृति बनाई जो काफी

चर्चित रही। नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 को बिहार के मुंगेर जिले में स्थापत्य शिल्पी पूर्णचंद्र बोस और क्षेमाणी के घर हुआ। पैतृक गांव बंगाल के हुगली में था।

बचपन से ही मूर्ति कला और चित्र कला गहरी रुचि को देखते हुए उनके माता-पिता ने कोलकाता के कला विद्यालय में प्रवेश दिलवाया। आधुनिक भारतीय कला के महानायक नंदलाल बोस ने चित्रकारों और कला अध्यापन के अतिरिक्त तीन पुस्तिकाएं रूपावली, शिल्प कला और शिल्प चर्चा भी लिखीं। 1930 में जब महात्मा गांधी को दांडी मार्च के दौरान गिरफ्तार किया गया था, तब नंदलाल बोस ने चित्र बनाया, जिसमें गांधी जी अपनी लाठी के साथ चलते हुए दिखाए गए। यहां से नंद लाल बोस की स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी शुरू हुई। नंदलाल बोस को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य रहे नंदलाल बोस ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

25 अगस्त 2019 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदलाल बोस को याद किया था। उन्होंने बताया कि गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन से पहले 1937-38 में महात्मा गांधी ने शांति निकेतन कला भवन के तत्कालीन प्रिंसिपल नंदलाल बोस को आमंत्रित

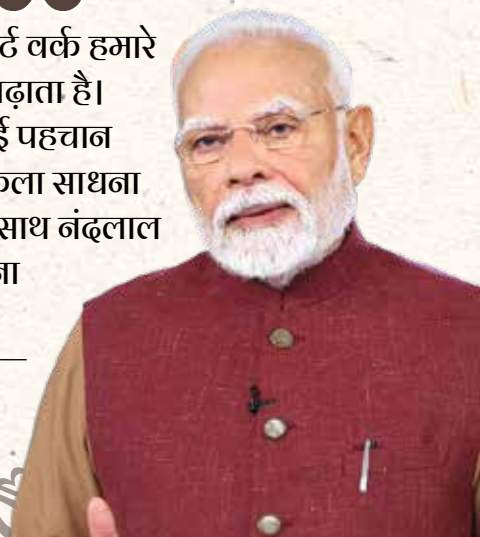




“

नंदलाल बोस का आर्ट वर्क हमारे संविधान की शोभा बढ़ाता है। संविधान को एक नई पहचान देता है। उनकी इस कला साधना ने संविधान के साथ-साथ नंदलाल बोस को भी अमर बना दिया है।

-नरेंद्र मोदी,
प्रधानमंत्री



किया था। गांधीजी चाहते थे कि वे भारत में रहने वाले लोगों की जीवनशैली को कला के माध्यम से दिखाएँ और उनकी इस आर्ट वर्क का प्रदर्शन अधिवेशन के दौरान हो। उन्होंने हरिपुरा के आसपास के गांव का दौरा किया और आखिर में ग्रामीण भारत के जीवन को दर्शाते हुए कुछ आर्ट कैनवास बनाये। इस अनमोल कलाकारी की 2019 में प्रसिद्ध कला प्रदर्शनी वेनिस बिनाले में जबरदस्त चर्चा हुई थी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नंदलाल बोस को याद किया था। उन्होंने कहा था कि नंदलाल बोस, गुरुवर रवींद्रनाथ टैगोर के अंतर्वासी थे और बहुत बड़े कलाकार थे। लिखे गए संविधान के अनुरूप नंदलाल बोस ने इतिहास, धर्म, संस्कृति और परंपरा एवं मानव जीवन को उच्च मूल्य देने वाली घटनाओं को यहां चित्र रूप

में उकेरा। यहां भगवान राम, बुध और महावीर हैं तो गुरुकुल से हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए इसका संदेश भी मिलता है। भगवत गीता के संदेश के चित्र के साथ शिवाजी और लक्ष्मीबाई को भी यहां पर स्थान देकर देशभक्ति का पाठ पढ़ाया गया है। प्रचीन शिक्षा पद्धति का स्मरण कराने वाले गुरुकुल के साथ ही नटराज का चित्र बताता है कि जीवन में संतुलन कैसा होना चाहिए।

इतना ही नहीं, 26 जनवरी 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की झांकी में संविधान के 75 वर्षों के गौरवशाली सफर का प्रस्तुतीकरण किया गया था। उसमें भी नंदलाल बोस की कलाकृतियों को मूर्ति कला पैनलों पर प्रमुखता से दर्शाया गया था। 16 अप्रैल 1966 को नंदलाल बोस का निधन हो गया। ■

आतंकवाद पर दो-टूक षडयंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा...

राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के प्रति संकल्प के अनुरूप केंद्र सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त संदेश दिया। बीते 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किले के पास हुई आतंकवादी घटना के विरुद्ध देश एकजुट है तो दुनिया ने भी भारत के प्रति अपना समर्थन जताया है। इस कायरतापूर्ण और घृणित कृत्य के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “इस षडयंत्र के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा!”

आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट है। वह अमन-शांति का पैरोकार है और युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को नासूर भी नहीं बनने देगा। बीते 11 वर्षों में आतंकवाद पर तीन बड़े स्ट्राइक- उरी सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर, उस संकल्प व प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आतंकवादियों ने जब भी भारत की सुरक्षा-संप्रभुता को चुनौती दी है, भारत के 140 करोड़ नागरिकों ने एकजुटता के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब दिल्ली में लाल किले के पास हुई आतंक की कारगराना हरकत पर बेहद संयमित रुख दिखाया है और सभी पहलुओं की गहन पड़ताल के बाद मामले की आगे की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआई) को सौंप दी गई है।

भूटान से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली में लाल किले के पास कार विस्फोट की आतंकवादी घटना में मारे गए लोगों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया। मंत्रिमंडल ने मृतकों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा।

प्रस्ताव पारित

- 10 नवंबर 2025 की शाम को लाल किले के पास कार विस्फोट के माध्यम से देश-विरोधी ताकतों द्वारा जघन्य आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया। इस विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई और अनेक लोग घायल हुए।
- मंत्रिमंडल ने इस घटना में मरने वाले लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की।
- मंत्रिमंडल ने सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करने के साथ-साथ चिकित्सा कर्मियों और पीड़ितों की सहायता एवं देखभाल में योगदान देने वाले एवं आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मियों के त्वरित प्रयासों की सराहना की।
- मंत्रिमंडल ने इस कायरतापूर्ण और घृणित कृत्य की कठोर शब्दों में निंदा की।
- मंत्रिमंडल ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता की नीति के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया।
- मंत्रिमंडल ने दुनिया भर की कई सरकारों से प्राप्त एकजुटता और समर्थन के बयानों के लिए भी आभार प्रकट किया।
- मंत्रिमंडल ने अधिकारियों, सुरक्षा एजेंसियों और नागरिकों द्वारा साहस और करुणा के साथ की गई समयबद्ध और समन्वित प्रतिक्रिया की सराहना की। विपत्ति की इस घड़ी में उनका समर्पण और कर्तव्य भावना अत्यंत सराहनीय है।
- मंत्रिमंडल ने जांच अत्यंत तत्परता और पेशेवर ढंग से करने के निर्देश दिए ताकि अपराधी, उनके सहयोगी और प्रायोजकों की पहचान कर उन्हें शीघ्र न्याय के कटघरे में लाया जा सके। सरकार सर्वोच्च स्तर पर लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है।
- मंत्रिमंडल सरकार की इस अटूट प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया कि वह सभी भारतीयों के जीवन और कल्याण की रक्षा करेगी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के प्रति उसके संकल्प के अनुरूप है।



“

हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जायेंगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बरखा नहीं जायेगा।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
(भूटान में एक कार्यक्रम के दौरान)

दिल्ली में 10 नवंबर की शाम हुई आतंकी वारदात की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच एवं एनआईए, एनएसजी के साथ-साथ फोरेसिक (एफएसएल) की टीम मौके पर पहुंच गई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तत्काल ही कमान संभाल ली। उन्होंने इस वारदात के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए तभी स्पष्ट किया कि सभी दृष्टिकोण से इस घटना की जांच की जा रही है। गृहमंत्री तत्काल घायलों से मिलने अस्पताल पहुंच गए और वहां से सीधे घटनास्थल का दौरा कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भूटान से लौटते ही सीधे अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और दोहराया कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। ■

वंदे मातरम के 150 वर्ष का स्मरणोत्सव

वंदे मातरम...

आजादी के परवानों का तराना

वंदे मातरम - “मां, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ”, यह शब्द एक मंत्र, एक ऊर्जा और एक संकल्प है। हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भरता है। भविष्य को यह नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प या लक्ष्य नहीं, जो हम भारतवासी पा न सकें। विरोध और देशभक्ति का प्रतीक वंदे मातरम के 150वें वर्ष में साल भर चलने वाले स्मरणोत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर को नई दिल्ली में किया शुभारंभ...

एकता, विरोध और राष्ट्रीय गौरव की स्थायी विरासत एवं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का स्मरणोत्सव 7 नवंबर, 2026 तक मनाया जाएगा। देशभर में यादगार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं जिसकी शुरुआत 7 नवंबर, 2025 को हुई। मुख्य कार्यक्रम के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्थानों पर ‘वंदे मातरम’ के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन किया गया। वंदे मातरम की भावना को आज के भारत के संदर्भ में नए सिरे से सामने रखने के साथ ही इन समारोहों के माध्यम से देश के गौरवशाली अतीत को उसके एकजुट,

आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ने का प्रयास है। भारत सरकार इसे चार चरणों में मनाएगी।

वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश भी दिया कि जो लोग राष्ट्र को केवल एक भू-राजनीतिक इकाई के रूप में देखते हैं, उनके लिए राष्ट्र को मां मानने का विचार आश्चर्यजनक लग सकता है लेकिन भारत अलग है। भारत में, मां जन्म देने वाली, पालन-पोषण करने वाली और जब उसकी संतान संकट में होती है, तो वह संकटों को हरने वाली भी होती है। मां भारती अपार शक्ति रखती है,





...और यूँ राष्ट्रीय गीत बना वंदे मातरम

भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम...यह रचना, अमर राष्ट्रगीत के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। राष्ट्रीय पहचान और सामूहिक भावना का चिरस्थायी प्रतीक है। 'वंदे मातरम' पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुआ था। बाद में, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने उपन्यास 'आनंदमठ' में शामिल किया। रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया था। 24 जनवरी, 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में एक बयान दिया... "जन गण मन नाम के शब्दों और संगीत से बनी रचना भारत का राष्ट्रगान है, जिसमें सरकार जरूरत पड़ने पर शब्दों में बदलाव कर सकती है और वंदे मातरम गीत, जिसने भारत के स्वाधीनता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसे जन गण मन के बराबर सम्मान दिया जाएगा। उसका दर्जा भी उसके बराबर होगा। मुझे आशा है कि इससे सदस्य संतुष्ट होंगे।" उनके बयान को अपनाया गया और रवींद्रनाथ टैगोर रचित जन-गण-मन को स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान और बंकिम चंद्र रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया।



वंदे मातरम, स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों का गीत होने के साथ-साथ शाश्वत प्रेरणा का भी काम करता है। हमें न केवल यह याद दिलाता है कि हमने स्वतंत्रता कैसे हासिल की, बल्कि यह भी बताता है कि हमें इसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए। जब भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, यह शब्द सहज रूप से हमारे दिलों से उठते हैं - भारत माता की जय! वंदे मातरम!

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



विपत्ति में मार्गदर्शन करती है और शत्रुओं का नाश करती है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति के दिव्य अवतार के रूप में देखने की धारणा ने एक ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से शामिल करने का संकल्प लिया गया था। पीएम मोदी कहते हैं कि इस दृष्टिकोण ने भारत को एक बार फिर एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखने में सक्षम बनाया जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे हो।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पूरे मूल गीत की पंक्तियों... त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरण-धारिणी कमला कमल-दल-विहारिणी वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम् नमामि कमलाम् अमलां अतुलाम् सुजलां सुफलाम् मातरम्, वंदे मातरम्! का हवाला देकर पीएम मोदी ने यह बताया कि भारत माता विद्या दायिनी सरस्वती भी है, समृद्धि दायिनी लक्ष्मी भी हैं और अस्त्र-शास्त्रों को धारण करने वाली दुर्गा भी हैं। हमें ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करना है जो ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में शीर्ष पर हो, जो विद्या एवं विज्ञान की ताकत से समृद्धि के शीर्ष पर हो और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर भी हो। फौज के जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू होने के 11 वर्ष भी 7 नवंबर को ही पूरे हुए हैं। जब हमारी सेनाएं, दुश्मन के नापाक इरादों को कुचल देती हैं, जब आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ी जाती है, तो देश के सुरक्षाबल एक ही मंत्र से प्रेरित होते हैं और वो मंत्र है - वंदे मातरम्! ■



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

सहकारिता

समृद्ध समाज की सशक्त नींव



अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

सहकारी समितियाँ एक बेहतर
दुनिया का निर्माण करती हैं



अल्पानाम् अपि वस्तूनाम्, संहतिः कार्य साधिका॥

अर्थात्, छोटी-छोटी वस्तुएं, थोड़े-थोड़े संसाधन भी जब साथ जोड़ दिए जाते हैं, तो उनसे बड़े-बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में कही गई यह बात भारत की प्राचीन व्यवस्था- सहकारिता के लिए बेहद सटीक है। भारत में दुनिया की एक चौथाई से भी अधिक सहकारी समितियां हैं और लगभग एक तिहाई भारतीय ग्रामीण जनसंख्या सीधे तौर पर इनसे अपनी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के लिए जुड़ी हुई है। ऐसे में दशकों से भारतीय संस्कृति का प्राण रही सहकारिता के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने बीते कुछ वर्षों में आमूल-चूल परिवर्तन कर नई ऊर्जा का संचार किया है। इससे अब सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन बनकर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को कर रहा है साकार...

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष- 2025 के समापन के लिए इससे बड़ा गौरव का क्षण क्या हो सकता है कि भारत की दो सहकारी समिति- अमूल और इफको को दुनिया की शीर्ष 10 सहकारी समितियों में प्रथम और द्वितीय स्थान मिला है। इतना ही नहीं, अमूल का पंजीकरण भी त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में 14 दिसंबर 1946 को हुआ था। गौरवमयी उपलब्धियों के साथ बने इस अद्भुत संयोग के अवसर पर आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार ने किस तरह नीतिगत सुधारों और पहल से सहकारिता के आंदोलन को संस्थागत रूप दिया है और 2047 के विकसित भारत के स्वप्न को कर रही है साकार...



भारत के लिए गर्व का क्षण!

अमूल और इफको को विश्व की शीर्ष दस सहकारी संस्थाओं में प्रथम दो स्थान प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। यह अमूल से जुड़ी लाखों महिलाओं के अथक समर्पण और इफको में योगदान देने वाले किसानों के लिए सम्मान है। यह सहकारी संस्थाओं की असीम संभावनाओं का भी प्रमाण है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता के वैश्विक मॉडल में परिवर्तित कर रहे हैं।

बीते 4 नवंबर को देश के प्रथम केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के इस संदेश में भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व सहकारिता में नई ऊर्जा का संचार था... सहकारिता के मूलभूत भारतीय विचार की विशालता का दर्शन था... सामूहिकता की शक्ति का उत्कृष्ट प्रदर्शन था... भारतीयता के सामर्थ्य से भरी जीवनशैली का परिचय था... सहकार से समृद्धि के राष्ट्रीय मंत्र का गौरव गान निहित था। यह दोनों उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प की सिद्धि का भी परिचायक है, जिसमें उन्होंने 22 फरवरी 2024 को अमूल के एक कार्यक्रम में कहा था, “आज अमूल दुनिया की आठवीं सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है। आपको इसे जल्द से जल्द दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी बनाना है। सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी है और यह मोदी की गारंटी है।” प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प दूसरे वर्ष में ही साकार हो गया, जो इस बात का परिचायक है कि बीते कुछ वर्ष पहले ही अस्तित्व में आए सहकारिता मंत्रालय ने औपचारिक रूप से सहकारिता क्षेत्र को कैसे एक नई दिशा दी है। इसी का परिणाम है भारत की दो सहकारी संस्थाएं दुनिया में शीर्ष पायदान पर पहुंची है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, “अमूल और इफको को बधाई। भारत का सहकारी क्षेत्र बहुत ऊर्जावान है और अनेक लोगों की जिंदगी में बदलाव भी ला रहा है। हमारी सरकार आने वाले समय में इस क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठा रही है।”

सहकारिता से समृद्धि

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025

- सहकारी क्षेत्र के तेज, समग्र और व्यवस्थित विकास का रोडमैप।
- लक्ष्य: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और युवाओं को जोड़ना।

50 करोड़ लोगों को 10 वर्षों में सहकारी ढांचे से जोड़ना और आर्थिक योगदान तीन गुना करना।

- हर जिले में बहुउद्देशीय पैक्स पर आधारित एक मॉडल को ऑपरेटिव गांव होगा।
- डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से 'श्वेत क्रांति 2.0'। महिला सशक्तीकरण और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
- दलहन, तिलहन, मक्का और मोटा अनाज की पैदावार बढ़ाकर खाद्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा।

लक्ष्य 10 वर्षों में

6 | 16 | 82

मिशन पिलर | उद्देश्य | रणनीतियां

के जरिए होगा हासिल।



अब इस गौरवगाथा को उदाहरणों से समझते हैं...

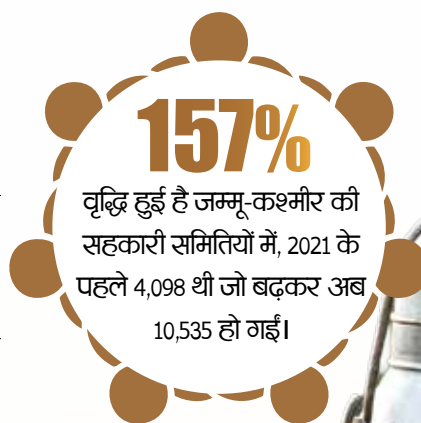
अमूल आज देश में श्वेत क्रांति की वाहक बनी है। 36 लाख किसान सदस्य, 18 हजार ग्रामीण समितियां और 18 जिला संघों के माध्यम से अमूल आज देशभर में 3.5 करोड़ लीटर दूध रोजाना इकट्ठा करती है। वर्ष 2024-25 में अमूल का टर्नओवर 90 हजार करोड़ रुपये को पार कर गया जो यह बताता है कि 36 लाख किसान, जिनमें 65 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं, एक साथ छोटी पूंजी से

गांव-गरीब-किसान के जीवन में आ रहा है बदलाव

- सहकारिता मंत्रालय देश के गरीब, किसान और ग्रामीणों के जीवन में बदलाव ला रहा है।
- PACS के बायलॉज में संशोधन के बाद देश भर के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के निरीक्षकों का प्रशिक्षण पूरा।
- PACS को कॉमन सर्विस सेंटर, माइक्रो एटीएम, हर घर नल, बैंक मित्र सहित अन्य 25 गतिविधियों से जोड़ा गया है।
- जन औषधि केंद्र की सेवाएं दे रहे PACS, किरायाती दवाओं की उपलब्धता के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं।

केंद्र सरकार की बड़ी प्राथमिकता बनी सहकारिता

- देश में पहली बार सहकारी समितियों का डेटा बैंक बनाया गया है। डेटाबेस में 30 विभिन्न क्षेत्रों की 8.44 लाख सहकारी समितियों के डेटा शामिल हैं जिनके लगभग 32 करोड़ सदस्य हैं।
- 27% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी सहकारी समितियों में महाराष्ट्र की है, 10% के साथ दूसरे नंबर पर गुजरात है।
- 23% की हिस्सेदारी सहकारी समितियों में आवास सहकारी समितियों की है जो सबसे अधिक है, उसके बाद डेयरी की 18% और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की 13% है।



भारत की 20% से अधिक जनसंख्या किसी न किसी रूप में सहकारी आंदोलन से जुड़ी है जबकि वैश्विक औसत केवल 12% है।

90 हजार करोड़ के टर्नओवर के साथ इतना बड़ा कोऑपरेटिव सफलतापूर्वक इतने सालों से चला रहे हैं। यह देश में कोऑपरेटिव के लिए उपलब्ध अपार संभावनाओं को बताता है। अमूल के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, “भारत की आजादी के बाद, देश में बहुत से ब्रांड बने लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं। आज अमूल भारत के पशुपालकों के सामर्थ्य की पहचान बन चुका है। अमूल यानी विश्वास। अमूल यानी विकास। अमूल यानी जनभागीदारी।

अमूल यानी किसानों का सशक्तीकरण। अमूल यानी समय के साथ आधुनिकता का समावेश, अमूल यानी आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा, अमूल यानी बड़े सपने, बड़े संकल्प और उससे भी बड़ी सिद्धियां।”

इसी तरह इफको ने 41 हजार करोड़ रुपये का टर्नओवर और 3 हजार करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है। इफको कोऑपरेटिव सोसायटीज की सोसायटी है। देशभर में 35 हजार कोऑपरेटिव सोसायटी, जिनमें अधिकतर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

पैक्स को बहुउद्देशीय, बहुआयामी और पारदर्शी संस्था बनाने की पहल

प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) से 13 करोड़ से अधिक किसान सदस्य जुड़े हैं। पैक्स को बहुउद्देशीय, बहुआयामी और पारदर्शी संस्था बनाने के लिए आदर्श उपविधियां बनाई गईं। महिला और एससी एवं एसटी को प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स सदस्यता को अधिक समावेशी एवं व्यापक बनाने की बात जोड़ी जोड़ी गई। पैक्स को 25 आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर बहु सेवा केंद्र के रूप में बदला जा रहा है। इनके माध्यम से अब 300 से अधिक सरकारी योजना व सेवाएं यहां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

- 32 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक इसे अपनाया है। -

कंप्यूटरीकरण से पैक्स का सशक्तीकरण

2,925 करोड़ रुपये के खर्च के साथ पैक्स के कंप्यूटरीकरण परियोजना को मंजूरी दी गई।

73,493 पैक्स की परियोजना का अनुमोदन, करीब 60 हजार ऑनबोर्ड हो चुके। 30 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हार्डवेयर की खरीद कर ली गई है।



सहकारिता के दायरे में पंचायत और गांव

सभी पंचायत और गांव को सहकारी संस्थाओं के दायरे में लाने के लिए नए पैक्स, डेयरी और मछली पालन सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। 15 फरवरी 2023 को योजना की शुरुआत से 15 अगस्त 2025 तक देश में कुल 24,417 नई पैक्स, डेयरी और मछली पालन सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं।

सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना

- कई योजना और मिशन को जोड़कर पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए गोदाम, कस्टम हायरिंग केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई और अन्य कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है ताकि अनाज की बर्बादी को रोका जा सके एवं परिवहन लागत में कमी आए।
- 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदाम निर्माण का काम पायलट प्रोजेक्ट में पूरा हो चुका है। अब इसे विस्तार देते हुए 500 से अधिक पैक्स को गोदामों के निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है।
- 225 पैक्स में निर्मित होने वाले गोदाम को राज्य सरकार, नेफेड, एनसीसीएफ ने किराये का आश्वासन दिया है। 129 अन्य पैक्स में निर्माण कार्य शुरू हुआ है जिनमें 65 का निर्माण पूरा हो चुका है।
- इस योजना के लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) में वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने, निर्माण लागत और सब्सिडी से संबंधित कुछ संशोधन किए गए हैं।

(पैक्स) और मार्केटिंग से जुड़ी हुई समितियां इसके सदस्य हैं। लगभग 5 करोड़ से अधिक किसान इन समितियों के माध्यम से इफको के सदस्य बने हैं। आज इफको 93 लाख मीट्रिक टन यूरिया और डीएपी का उत्पादन कर देश की हरित क्रांति का स्तंभ बन गया है। इफको का नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, ब्राजील, ओमान, अमेरिका, जॉर्डन और दुनिया के 65 देशों में निर्यात हो रहा है।

अब अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए) ने अमूल को विश्व रैंकिंग में प्रथम और इफको को दूसरे स्थान पर रखा है, जो दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का विचार और संस्कृति प्रभावशाली रूप से जीवंत है। इतना ही नहीं, भारत के उरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने उद्यमी सहकारी पुरस्कार श्रेणी में 2023 में एशिया पैसिफिक कोऑपरेटिव एक्सीलेंस अवार्ड जीता था।

कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में पैक्स

ग्रामीण स्तर पर पैक्स की पहुंच को देखते हुए बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड तथा रेल, बस व हवाई टिकट जैसी 300 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराने में इन्हें सक्षम बनाने के लिए एक बहु मंत्रालय व बहु एजेंसी समझौता किया गया। 50,355 पैक्स ने 10, नवंबर 2025 तक ग्रामीण जनता को कॉमन सर्विस सेवाएं देनी शुरू कर दी हैं।

- 1863 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का पंजीकरण पैक्स ने किया है। यह किसानों को बाजार लिंकेज दिलाने और उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने में सहायक बनेगा।
- खुदरा पेट्रोल-डीजल आउटलेट के लिए पैक्स को प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है। 27 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के 393 पैक्स ने आवेदन किए हैं। वहीं पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप को खुदरा आउटलेट में परिवर्तन करने का विकल्प दिया गया है।
- सरकार ने अब पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने का आवेदन करने की अनुमति दे दी है।
- पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जलापूर्ति के ऑपरेशन और रखरखाव का काम करने के लिए पात्र माना गया है। इसके लिए 539 पैक्स को चिन्हित भी कर लिया गया है।
- पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी पैक्स से जोड़ा गया है। शुरुआत में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए 100 नगरों का चयन किया गया है।

36,592

पैक्स अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं ताकि देश में किसानों को उर्वरक और अन्य संबंधित सेवाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

सहकारिता की ऐसी सशक्त और प्रेरक गाथा की सूची बेहद लंबी है और इसका महत्व देश-दुनिया में मौजूदगी के आंकड़े बताते हैं। देश में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिसमें 30 करोड़ से अधिक लोग इसके सदस्य बने हुए हैं और यह लगभग 30 क्षेत्रों में व्यापकता से काम करते हैं। देश में प्रत्येक पांचवां व्यक्ति सहकारिता से जुड़ा हुआ है। सहकारिता गरीबों और पिछड़ों के विकास का माध्यम बन चुकी है। सहकारिता ऐसा क्षेत्र बन गया है,

संगठित सहकारी संस्था के सदस्य बन सकेंगे 20 लाख डेयरी किसान

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जुलाई, 2025 में सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड नाम से एक बहुराज्य सहकारी संस्था का शुभारंभ किया। इसकी प्रारंभिक पूंजी 200 करोड़ है। इसमें 20 राज्य के 20 हजार से अधिक गांव के 20 लाख से अधिक डेयरी किसान सदस्य बन सकेंगे। इस फेडरेशन के माध्यम से किसानों को दूध की सुनिश्चित खरीद, बेहतर पशु चिकित्सा देखभाल, पशुओं के पोषण में वृद्धि और आधुनिक डेयरी तकनीकों का लाभ मिलेगा। मजबूत कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज केंद्र और कुशल प्रसंस्करण सुविधाओं में निवेश से गुणवत्ता मानकों को और अधिक मजबूती मिलेगी। सुरक्षित और स्वच्छ डेयरी उत्पादों की मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी।



जो देश में एक प्रकार से प्रत्येक परिवार को छूता है। आज देश में लगभग 91% गांव यानी करीब-करीब प्रत्येक गांव में कोई न कोई ऐसी इकाई है जो सहकारिता के माध्यम से कृषि विकास, ग्रामीण विकास और स्वरोजगार के काम में जुटी हुई है और देश के विकास में अपना योगदान दे रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है और स्वरोजगार के साथ-साथ छोटी उद्यमिता का भी विकास हो रहा है। सामाजिक समावेशन बढ़ रहा है तो इनोवेशन और

सहकारी समितियां

बढ़ावा देने वाली पहलें

सहकारिता आंदोलन को मजबूती देने के लिए मंत्रालय ने 100 से अधिक पहलें कीं। 6 जुलाई, 2025 को राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 लॉन्च की गई। साथ में, सहकारिता से समृद्धि के मंत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और पहल की तो आयकर, जीएसटी सहित कई कर राहत भी दी गई।

1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक की आय वाली सहकारी समितियों पर लगने वाला कर 12% से घटाकर 7% कर दिया है। इससे सहकारी समितियों पर कर भार कम हुआ है।

- सहकारी समिति द्वारा 2 लाख रुपये तक के नकद लेनदेन को आयकर जुमाने से मुक्त किया गया। पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की नकद जमा राशि एवं भुगतान की सीमा 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई।
- नई विनिर्माण सहकारी समितियों पर 30 फीसदी की पूर्व दर की तुलना में 15 फीसदी सपाट निम्न कर लगाया गया।



- सहकारी समितियों के न्यूनतम वैकल्पिक कर को 18.5 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया।
- सहकारी चीनी मिलों को अप्रैल, 2016 से किसानों को गन्ने के उच्चतर मूल्य का भुगतान करने या राज्य सलाह मूल्य तक भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त कर नहीं देना पड़ेगा।

देश में आज 8.44 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं सक्रिय हैं जिनसे लगभग 32 करोड़ लोग प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से जुड़े हैं। इतना ही नहीं करीब 94 प्रतिशत किसान किसी न किसी रूप में सहकारी समितियों से जुड़े हैं।



- शीरा पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% किया गया जिससे उच्चतर दरों पर शीरा की बिक्री करके सहकारी चीनी मिलें सदस्यों के लिए अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगी।
- सहकारी चीनी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पूर्व गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति दी। इससे 46 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राहत की उम्मीद। साथ ही, सहकारी चीनी मिलों के सशक्तीकरण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की लोन योजना शुरू की गई।
- एथेनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को प्राथमिकता देने के साथ एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की एथेनॉल खरीद में सहकारी चीनी मिलों को निजी कंपनियों के समरूप रखा गया।
- सहकारिता क्षेत्र में 60 से ज्यादा नीतिगत सुधार किए हैं ताकि पारदर्शिता, रोजगार और स्थिरता बढ़े।
- डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को केंद्रीय व राज्य सहकारी बैंक का बैंक मित्र भी बनाया जा

अनुसंधान में कई नए मानक गढ़े जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर में सहकारिता क्षेत्र 30 लाख सहकारी समितियों के माध्यम से 12 प्रतिशत से अधिक मानवता को जोड़ती है, जिसमें 300 सबसे बड़ी सहकारी समितियां 2,409.41 बिलियन अमरीकी डॉलर का कारोबार करती हैं। वह 28 करोड़ लोगों को गुणवत्तापूर्ण रोजगार और काम के अवसर प्रदान करके सतत आर्थिक विकास को भी

"भारत में सहकारिता ने विचार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तीकरण तक का सफर किया है। कोऑपरेटिव से ग्लोबल को-ऑपरेशन को नई ऊर्जा मिल सकती है।"

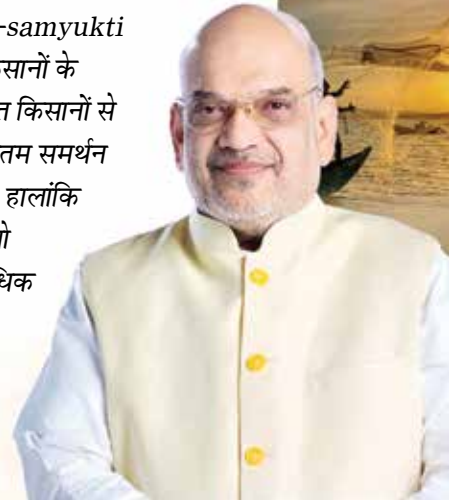
- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

रहा है। इन्हें डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं देने के लिए माइक्रो एटीएम भी दिए जा रहे हैं। गुजरात में करीब 10 हजार माइक्रो एटीएम वितरित किए जा चुके हैं।

- सहकारी बैंकों की पहुंच बढ़ाने और डेयरी सहकारी समिति सदस्यों को आवश्यक लिविडिटी उपलब्ध कराने के लिए रुपये किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं।
- 1,000 मौजूदा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को मात्स्यिकी उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) के रूप में परिवर्तित करने का काम भी शुरू किया गया है। इनके लिए क्लस्टर बेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा व्यवसाय योजना तैयार की जा रही है। 70 एफएफपीओ इससे पूर्व में पंजीकृत, ताकि मछुआरों को बाजार लिंकेज और प्रसंस्करण सुविधाएं मिलने में आसानी हो।
- 2025-26 से 2028-29 की अवधि के लिए 2,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक केंद्रीय योजना 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को अनुदान सहायता' को मंजूरी दी गई है। इसकी मदद से एनसीडीसी चार वर्षों में खुले बाजार से लगभग 20,000 करोड़ रुपये जुटा सकेगा।
- देश भर में डेयरी, पशुपालन, मात्स्यिकी, चीनी, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और शीतगृह, श्रम और महिला-नेतृत्व वाली सहकारी समितियों जैसे विविध क्षेत्रों की 13,288 सहकारी समितियों के लगभग 2.9 करोड़ सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है।

किसानों की आत्मनिर्भरता की राह...

सहकारिता मंत्रालय ने देश में दलहन (तुअर, मसूर और उड़द) का उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भरता अभियान शुरू किया है। साथ ही, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मक्के के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए एनसीसीएफ और नेफेड को जिम्मेदारी दी गई है। एनसीसीएफ e-samyukti और नेफेड ने e-samridh पोर्टल की शुरुआत किसानों के पंजीकरण के लिए कर दी है। इस पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से तुअर, उड़द, मसूर और मक्का की पूरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की गारंटी दी गई है। हालांकि अगर बाजार में कीमत एमएसपी से ज्यादा होती है तो किसान अपनी उपज को खुले बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। अभी तक e-samyukti पोर्टल पर 41 लाख 41 हजार से अधिक किसान और नेफेड के e-samridhi पोर्टल पर 11.07 लाख किसान पंजीकृत हैं।



- सहकारी समितियों को GeM पर 'खरीददार' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी गई, जिससे वे कृषि उत्पाद खरीद एवं अधिक पारदर्शिता के साथ लगभग 67 लाख वेंडरों से माल और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे। 574 से अधिक सहकारी समितियां ऑनबोर्ड हो चुकी हैं।
- सहकारी समितियों का मूल्यांकन और रैंकिंग करने के लिए सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क जनवरी, 2025 में लॉन्च की गई। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल 7 प्रमुख क्षेत्रों की रैंकिंग जेनरेट कर सकता है।
- बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्त करने, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने एवं निर्वचन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 में बहुराज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत संशोधन किया गया।
- सहारा समूह की सहकारी समितियों के 22.56 लाख वैध जमाकर्ताओं को 4,548 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एक पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से लौटाई जा चुकी है।

बढ़ावा देते हैं, जो दुनिया की नियोजित आबादी का 10 प्रतिशत है। सहकारिता के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, जिसका थीम है- सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं।

दरअसल, सहकारिता दशकों से भारतीय संस्कृति का प्राण रही है। यह विचार भारत का विचार है। भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व

ही सहकारिता है। भारत ने पूरी दुनिया को सहकारिता का विचार देने एवं सहकारिता को आगे बढ़ाने का काम किया है। दुनिया के लिए सहकारिता एक मॉडल है, लेकिन भारत के लिए यह संस्कृति का आधार और एक जीवनशैली है। सहकारिता वह शक्ति बन चुकी है जो व्यक्ति की शक्तियों को सामूहिक रूप से समाज की शक्ति में परिवर्तित करती है। यह भी कहा जा सकता है कि भारतीय



श्वेत क्रांति 2.0...

भारत के ग्रामीण परिवर्तन में एक नया अध्याय

देश के जिन हिस्सों में डेयरी सहकारी समितियां नहीं पहुंची हैं, वहां के किसानों तक इन समितियों की पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य श्वेत क्रांति 2.0 में रखा गया है। डेयरी सहकारी समितियों से जुड़ने के बाद किसानों को दूध की बिक्री के लिए बेहतर बाजार मिल सकेगा। श्वेत क्रांति 2.0 में सहकारी समितियों की पहुंच बढ़ाना, दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करना, ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर बनाना और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 की एसओपी लॉन्च कर दी है।

16,322 सहकारी दुग्ध समितियां अभी तक पंजीकृत की जा चुकी हैं।

डेयरी क्षेत्र में 'कचरे से कंचन' बनाने की पहल पर काम शुरू

श्वेत क्रांति 2.0 का एक मुख्य उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में एक ऐसा विकास मॉडल विकसित करना भी है जिसमें पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों का पुनः उपयोग और किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित की जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर डेयरी क्षेत्र में सस्टेनबिलिटी और सरकुलैरिटी के तहत डेयरी मूल्य श्रृंखला में जलवायु स्मार्ट तरीकों को अपनाना, संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना और नवीकरणीय संसाधनों के माध्यम से कम उत्सर्जन एवं आय सृजन वाले एक तंत्र का निर्माण करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। इस दिशा में तीन बहुराज्य सहकारी समितियों की व्यवहार्यता व स्थापना का काम प्रगति पर है।

- पशु आहार उत्पादन, रोग नियंत्रण और कृत्रिम गर्भाधान के लिए।
- गाय-भैंस के गोबर प्रबंधन के लिए।
- मृत मवेशियों की खाल, हड्डियों और सींगों के प्रबंधन के लिए।



भारत में को-ऑपरेटिव, हमारे डेयरी सेक्टर...
हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, एक नई
शक्ति दे रही है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



मजबूती देने और उसे घर-घर तक पहुंचाने के लिए वर्ष 2021 में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। पिछले 11 वर्ष में ग्रामीण भारत सड़क, आवास, दूरसंचार, बिजली, शौचालय, रसोई गैस जैसी बुनियादी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अभूतपूर्व विकास का साक्षी रहा है। इसने ग्रामीण आकांक्षाओं को कई गुणा बढ़ा दिया है। अब आधारभूत ढांचा तैयार हो चुका है। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत, संगठित और बाजार से जोड़ने की जरूरत है। ऐसे में सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन बनकर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में सहायक बनने को तैयार है।

भारत में सहकारिता आंदोलन

आजादी से पहले गुजरात के आणंद-खेड़ा जिले के कुछ किसान दूध का उत्पादन करते थे, वह दूध वहां से मुंबई की पॉलसन डेयरी में जाता था। एक दिन कुछ किसानों ने दूध के भाव में बढ़ोतरी की मांग की तो पॉलसन डेयरी ने दूध लेना बंद कर दिया। किसान असहाय हो गए और त्रिभुवन पटेल के नेतृत्व में सरदार पटेल के पास गए। सरदार पटेल ने कहा कि अगर आपको गुलामी ही करनी है तो शोषण को सहन करना पड़ेगा और ऐसा नहीं करना है तो आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए। अपने दूध का व्यापार खुद



दुनिया के लिए को-ऑपरेटिव्स एक मॉडल है, लेकिन भारत के लिए कोऑपरेटिव्स संस्कृति का आधार है, जीवन शैली है। आज हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

कीजिए। फिर त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में 14 दिसंबर 1946 को इतिहास रचा गया जब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन जिसे आमतौर पर अमूल के नाम से जाना जाता है, को बॉम्बे सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1925 के अधीन पंजीकृत किया गया। देश की पहली छोटी सी एक गांव

सहकारी बैंक

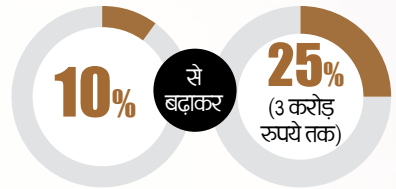
सरकार की पहलों से हो रहे सशक्त

सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से सहकारी बैंकों के सशक्तीकरण के लिए की गई पहलों में नई शाखाएं खोलने, ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति, आरबीआई में नोडल अधिकारी और आवास लोन की सीमा में वृद्धि जैसी अनेक पहलों की गई हैं।

- शहरी सहकारी बैंक को अब आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष का 10% या अधिकतम 5 शाखा खोलने के लिए पात्र माना गया है।
- शहरी सहकारी बैंकों को आरबीआई ने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाएं देने की अनुमति दे दी है। इन बैंक के खाताधारक अब घर पर ही नकद निकासी एवं जमा, केवाईसी, डिमांड ड्राफ्ट, जीवन प्रमाणपत्र जैसी बैंकिंग सुविधाएं ले सकते हैं।

- शहरी सहकारी बैंक अब वित्तीय सुदृढ़ एवं सुप्रबंधित मानदंड को पूरा करने और न्यूनतम आवश्यक जमा राशि बरकरार रखने पर आरबीआई की अनुसूची-II में शामिल होकर अधिसूचित का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।

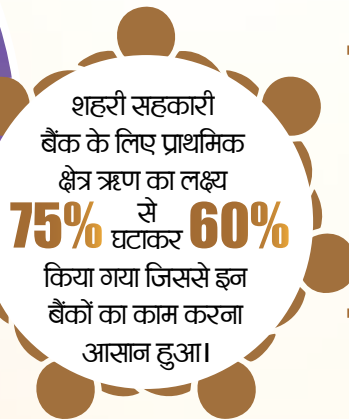
शहरी सहकारी बैंक के सदस्यों की बढ़ाई गई आवास लोन सीमा



- लोन सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये किया गया जिससे उच्च लोन मांग पूरा करने, व्यापार वृद्धि में मदद एवं एसएमई लोन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में यह बैंक सक्षम हुए हैं।



- आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए एक अंबेला संगठन की स्थापना को मंजूरी दी है जिससे लगभग 1,500 शहरी सहकारी बैंकों को आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- शहरी सहकारी बैंकों को अन्य बैंकों की तरह बकाया लोन का वन टाइम सेटलमेंट करने की अनुमति दी गई है। सहकारी बैंक अब बोर्ड अनुमोदित नीतियों के माध्यम से तकनीकी राइट ऑफ करने के साथ-साथ उधारकर्ताओं को एक प्रक्रिया भी उपलब्ध करा पा रहे हैं।
- ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास लोन की सीमा ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपये किया गया।



की कोऑपरेटिव बनी, जिसमें ढाई सौ लीटर दूध एकत्र होता था। वहां से लेकर विश्व का सबसे मजबूत कोऑपरेटिव ब्रांड अमूल बनने की यह यात्रा त्रिभुवन दास पटेल के द्वारा हुई। त्रिभुवन दास, सरदार पटेल जैसे महान नेता के सान्निध्य में रहकर भारत के अंदर सहकारिता की नींव डालने वाले व्यक्तियों में से एक थे। गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ, जिसे हम अमूल के नाम से भी जानते हैं, वह त्रिभुवन दास के विचार की देन है।

2003 में अमूल का टर्नओवर देखें तो 2,882 करोड़ रुपये था, आज अमूल की बिक्री 90 हजार करोड़ रुपये पार कर गई है। यह कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से कई गुना ज्यादा है। इतने बड़े आंदोलन में किसी की भी शेयर पूंजी सौ रुपये से अधिक नहीं है। गरीब किसान महिलाओं ने सौ-सौ रुपये एकत्रित करके इसे बनाया है। आज जब इस चीज को आश्चर्यचकित होकर दुनिया देख रही है और अमूल ग्रुप का टर्नओवर दूध के अलावा इससे जुड़े अन्य



- शहरी सहकारी बैंकों के साथ नियमित संवाद के लिए आरबीआई में एक नोडल अधिकारी निश्चित किया गया।
- सहकारी बैंकों में 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' में ऑनबोर्ड करने के लिए लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से जोड़कर घटा दिया गया। इससे सदस्यों को घर बैठे बायोमेट्रिक के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं मिल रही हैं।
- नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एवं क्रेडिट सोसायटी के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों एवं सहकारी ऋण समितियों के सुधार पर एक टास्क फोर्स सरकार ने गठित की है जिसकी दो रिपोर्ट भी आ चुकी है।

आरबीआई ने कृषि सहकारी समितियों (डेयरी) के लिए प्राथमिक क्षेत्र ऋण सीमा बढ़ाई



- इस कदम से बैंक, इन समितियों को अधिक लोन सहायता दे सकेंगे जिससे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और ग्रामीण लोन प्रवाह बढ़ेगा।

कारोबार को मिलाकर 90 हजार करोड़ रुपये पार कर गया है। यह ग्रुप अकेले गुजरात की 36 लाख महिलाओं को स्वरोजगार दे रहा है।

वर्ष 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद सहकारी विकास को गति मिली, जिसमें योजना आयोग द्वारा निर्मित विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। 2002 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य देश में सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास को सुदृढ़ करना



भारत में आर्थिक प्रगति मापने के दो प्रमुख मानदंड हैं-सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार सृजन। दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना इन दोनों पहलुओं को मजबूत करने के लिए है, जिसका उद्देश्य पैक्स की आय बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करना है।

- अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

था। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए मंत्री स्तर के कार्य बल का गठन किया गया। इस कार्यबल ने सुझाव दिया कि राज्यों में समानांतर कानूनों की बजाय एक ही कानून लागू किया जाना चाहिए। भारत में सहकारी प्रणाली को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थात् ऋण और गैर ऋण सहकारी समितियां। क्रेडिट सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, उपभोग और विपणन के लिए किरायाती ब्याज दरों पर ऋण सुनिश्चित करती हैं, उपभोक्ता सहकारी समितियां रियायती दरों पर किसानों की उपभोग मांग को पूरा करती हैं। विपणन समितियां वस्तुओं के लेनदेन में बिचौलियों को खत्म करके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करती हैं। सहकारी समितियां कृषि और लघु उद्योग विपणन, प्रसंस्करण, वितरण और आपूर्ति से संबंधित कार्यकलाप भी करती हैं।

देश में लगभग 8 लाख से अधिक पंजीकृत सहकारी समितियां हैं, जिसमें 30 करोड़ से अधिक सदस्य हैं जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित कार्यकलापों में लगे हुए हैं। सहकारी क्षेत्र ने हमेशा देश में समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहकारी मॉडल भारतीय समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग को आर्थिक विकास का अग्रणी बनाकर व्यापक वित्तीय समृद्धि पैदा कर रहा है।

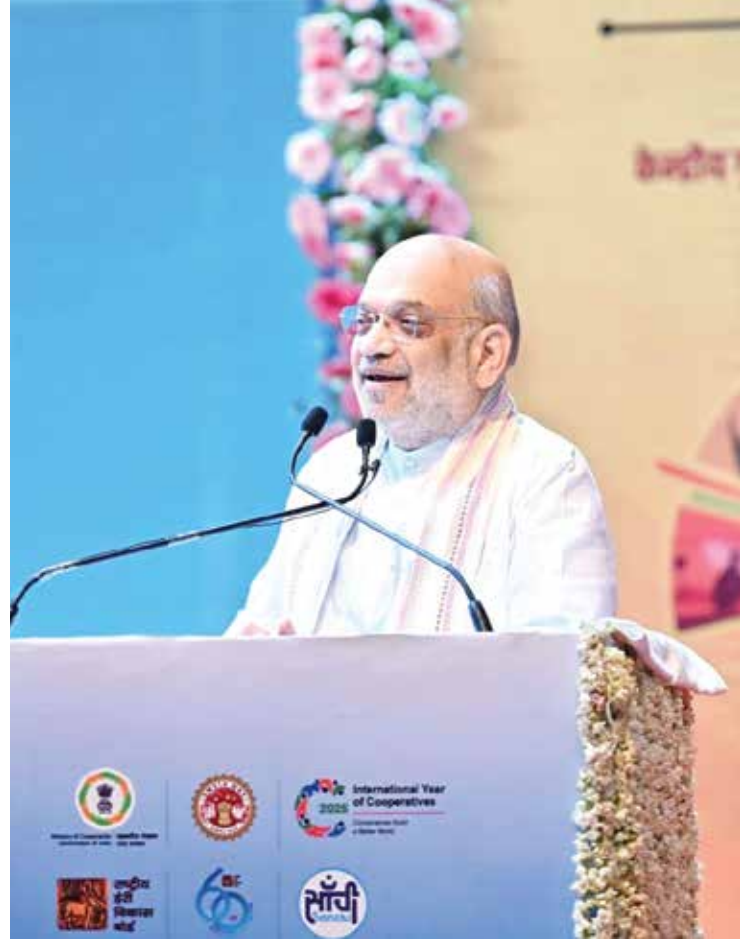
सहकार से समृद्धि के मंत्र से बना मंत्रालय

सहकारिता, भारत के मूलभूत चिंतन स्वभाव-संस्कार के अनुकूल व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के मंत्र को साकार करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 6 जुलाई 2021 को

नए मंत्रालय के रूप में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। इसका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी, नीतिगत ढांचा प्रदान करना था। देश में सहकारिता आधारित विकास मॉडल बहुत प्रासंगिक है। जहां प्रत्येक सदस्य अपनी जिम्मेदारी के अनुरूप काम करता है। नया सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए कारोबार में सुगमता, प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहुराज्यीय सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में अभूतपूर्व काम कर रहा है। सहकारिता आधारित अर्थव्यवस्था का मॉडल देश में प्राचीन काल से चला आ रहा है। वर्तमान समय में अमूल जैसे जन आंदोलन ने सहकारिता का लाभ गांव-गांव और परिवार-परिवार तक पहुंचाया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में सहकारिता आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ ही समुदाय आधारित विकासात्मक भागीदारी के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता का संकेत दिया था। सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण से सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दीर्घकालिक सोच और प्रशासनिक-नीतिगत सुधारों ने सहकारी क्षेत्र का कायाकल्प किया है।

सहकारिता क्षेत्र: पहले और अब

देश में 7 दशक से अधिक समय से किसान, ग्रामीण और कोऑपरेटिव नेतृत्व अलग से सहकारिता मंत्रालय की मांग कर रहे थे। जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया। सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद सहकारिता के विकास का नया अध्याय शुरू हुआ है। 7 दशक से अधिक समय तक इस क्षेत्र पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना दिया जाना चाहिए था। सहकारिता का आंदोलन भी अलग-अलग क्षेत्रों में समान रूप से नहीं चल रहा था। पश्चिम-दक्षिण में अच्छा चल रहा था, मध्य में मध्यम प्रकार का था, उत्तर में कमजोर था, पूर्व में स्थिति और कमजोर थी। अलग से सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद इस क्षेत्र पर संस्थागत तरीके से ध्यान दिया गया। सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर सहकारिता का डेटा बेस तैयार किया गया है। आज इसके जरिए कोई भी देख सकता है कि कहां कितनी कोऑपरेटिव है, डेयरी, पैक्स, मार्केटिंग, मत्स्य, हाउसिंग की स्थिति क्या है। इसके बाद केंद्र सरकार ने तय किया कि 2 लाख नए प्राथमिक कोऑपरेटिव



राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 देश में सतत सहकारी विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करती है। इस रोडमैप में जमीनी स्तर पर सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की योजनाओं के साथ समन्वय भी शामिल है। सहकारी समितियों के नेतृत्व में श्वेत क्रांति 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है।

- **अमित शाह**, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री



भारत टैक्सी

भारत का पहला सहकारिता आधारित मोबिलिटी प्लेटफार्म

सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, सहकारिता आधारित देश का पहला मोबिलिटी प्लेटफार्म है जिसका उद्देश्य चालकों को सशक्त बनाने के साथ ही जनता को किफायती और विश्वसनीय परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। सहकारिता, पारदर्शिता और साझा स्वामित्व पर आधारित सहकार टैक्सी, पारंपरिक राइड हेल्डिंग प्लेटफार्म का जनकेंद्रित विकल्प है। 'भारत टैक्सी' नाम से जल्द लॉन्च के लिए तैयार यह प्लेटफार्म भारत में आवागमन के परिदृश्य में एक बड़ा परिवर्तन लाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। इस कदम का उद्देश्य सहकारी-संचालित, पारदर्शी और नागरिक-प्रथम राइड-हेल्डिंग प्लेटफॉर्म के साथ मोबिलिटी इको-सिस्टम को बदलना है। इस परियोजना को राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के साथ ही इफको, नेफेड, अमूल, कृभको, एनडीडीबी, एनसीईएल और नबार्ड संयुक्त रूप से बढ़ावा दे रहे हैं।

सहकारी संस्थाएं देश में एक तिहाई चीनी उत्पादन, एक चौथाई उर्वरक उत्पादन, पांचवा हिस्सा कृषि लोन, धान व मछली की खरीद और 10वां हिस्सा दूध के उत्पादन और वितरण में योगदान देती हैं।

सोसाइटी पैक्स बनाए जाएंगे, ताकि देश में एक भी पंचायत ऐसा न रहे जहां पैक्स नहीं हो। केंद्र सरकार के प्रयास से आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पूर्वोत्तर से लेकर द्वारका तक, पूरे देश में केंद्र के मॉडल- पैक्स के बायलॉज मंजूर किए गए हैं।

इस बदलाव से 25 से अधिक आर्थिक क्रियाकलाप को पैक्स के साथ जोड़ा गया है। इसके अंदर चुनाव की पद्धति जुड़ी और इसके अंदर एक कॉमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डाला गया, जो देश की सभी भाषाओं में बना हुआ है। पैक्स लघु, मध्यम और दीर्घ अवधि के कृषि ऋण देता है। अब वह उन्नत बीजों का वितरण कर रहा है, फल-सब्जियों का उत्पादन करता है, मधुमक्खी पालन करता है, पैक्स मत्स्य सोसाइटी भी है, पैक्स डेयरी भी है, पैक्स रेशम उत्पादन के काम से भी जुड़ा है और पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर भी है।

आज देश के अंदर 50 हजार से अधिक पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 300 से अधिक सेवा और योजनाएं हैं।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण कराना हो, हवाई-रेलवे टिकट बुक कराना हो, कोई सत्यापन कराना हो, पैक्स के माध्यम से हो रहे हैं। देश में 36 हजार प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पैक्स काम कर रहे हैं। यहीं 4 हजार से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बन रही हैं। देश में बहुत सारे पैक्स अपना पेट्रोल पंप बना रहे हैं। एलपीजी वितरण के लिए कई पैक्स ने आवेदन किया है। अब तक अन्न भंडारण का काम जो निजी हाथों में चला गया था, अब पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पर भी काम हो रहा है। अब तक 500 चिन्हित पैक्स गोदाम में से 76 में काम भी शुरू हो चुका है। 11 पैक्स गोदाम का काम पूरा हो चुका है और पैक्स के माध्यम से खरीदा हुआ धान और गेहूं भंडारण से निकलकर प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त अनाज योजना के तहत 5 किलोग्राम पहुंचाया जा रहा है।

इन सभी काम के लिए कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर दिया गया है। सारा कारोबार ऑनलाइन हो चुका है। एक प्रकार से सहकारिता क्षेत्र में नई आधुनिक क्रांति आई है। दो लाख बहुदेशीय नए पैक्स बनने



3. भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL)



अंब्रेला संगठन के रूप में यह संस्था भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की योजना और नीतियों का लाभ उठाकर पैक्स के माध्यम से बुनियादी और सत्यापित बीजों का उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणन, खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग करती है।

परंपरागत बीजों के लिए छोटे किसानों के साथ भी अनुबंध करेगी जिससे उन्हें भी इसका फायदा मिल सके।

22,995

पैक्स व सहकारी समितियां बीबीएसएसएल की सदस्य बन चुकी हैं। 'भारत बीज' ब्रांड के अंतर्गत बीज लॉन्च किए हैं।

तीन राष्ट्र स्तरीय बहुराज्य सहकारी समितियों से समृद्धि का नया मार्ग

सहकारिता क्षेत्र, कृषि और किसानों की समृद्धि के लिए तीन राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों का गठन किया गया है।

1. राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड (NCOL)



जैविक उत्पादों का संकलन, प्रमाणीकरण, परीक्षण, खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग और उनकी मार्केटिंग सुनिश्चित करती है जिससे किसानों को उनके उत्पादों का अच्छा मूल्य मिल सके।

7,031

पैक्स व सहकारी समितियां सदस्य बन चुकी हैं।

उत्पाद 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड नाम से लॉन्च किए हैं। 25 जैविक उत्पाद दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपलब्ध हैं।

भारत ऑर्गेनिक्स के सभी उत्पादों का परीक्षण 245 से अधिक कीटनाशकों के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाता है।

2. राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL)



किसानों के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है जिसका पूरा मुनाफा किसानों को मिलता है।

- 9,425 पैक्स व सहकारी समितियां एनसीईएल की सदस्य बन चुकी हैं।
- 13.09 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादों जैसे चावल, गेहूं, मक्का, चीनी, प्याज, जीरा आदि का निर्यात किया है जिनका अनुमानित मूल्य 5,397 करोड़ रुपये है।

से संतुलित तरीके से देश का सहकारिता आंदोलन पुनः खड़ा होगा। आज जेम पोर्टल पर 550 से अधिक सहकारी समितियां पंजीकृत हो चुकी हैं। समितियों पर आयकर अधिभार 12 प्रतिशत से कम करके 7 प्रतिशत कर दिया गया है। मैट को 18.5 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत किया और धारा 269 एसटी के तहत 2 लाख रुपये से कम लेनदेन पर आयकर जुर्माने से छूट दी गई है। निर्माण करने वाली

सहकारी समितियों की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत की गई है। पैक्स और बाकी लोगों के लिए नकदी जमा रकम सीमा 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई। टीडीएस से मुक्ति की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये की गई। सहकारिता क्षेत्र में नई शुरुआत का ही परिणाम है कि सहारा समूह में लोगों के निवेश किए हुए धन की वापसी सुनिश्चित हो रही है। देश पर जब-जब

कोई विपदा आई है, सहकारिता आंदोलनों ने देश को उससे बाहर निकाला है। कोऑपरेटिव बैंक बिना मुनाफे की चिंता किए लोगों के लिए काम करते हैं क्योंकि, भारत के संस्कारों में सहकारिता है।

अब कोऑपरेटिव के आधार पर ओला, उबर जैसी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आ रही है जो कार-बाइक-ऑटो रिक्शा का भी पंजीकरण करेगी, उसका लाभ अब सीधे ड्राइवर को जाएगा। कोऑपरेटिव बीमा कंपनी भी बनने जा रही है जो सभी कोऑपरेटिव व्यवस्था का बीमा करेगी। संभव है कि यह निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी कोऑपरेटिव बीमा कंपनी बन जाएगी।

सहकारिता क्षेत्र की 'त्रिशक्ति'

सहकारी समितियों को जीवंत और सफल व्यावसायिक इकाइयों के रूप में परिवर्तित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय प्रतिबद्ध है। सहकारिता क्षेत्र, कृषि और किसानों की समृद्धि के लिए तीन राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों का गठन किया गया है। केंद्र ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) नाम से एक राष्ट्रीय कोऑपरेटिव संस्था बनाई है, जिससे लगभग 8 हजार से अधिक पैक्स जुड़ चुके हैं। इसके माध्यम से देश के किसानों के उत्पाद को विदेश में निर्यात किया जा रहा है। जिसका पूरा मुनाफा किसानों को मिलता है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड (NCOL) के माध्यम से किसानों के जैविक उत्पाद को खरीदकर, जांच कर, भारत ब्रांड नाम देकर पैकेजिंग कर बाजारों में बेचा जाता है। आज 5 हजार पैक्स के किसान अपने जैविक उत्पाद को इसके माध्यम से देश-विदेश के बाजारों में बेच रहे हैं। इसमें जैविक चावल, आटा, अनाज, बाजरा, चीनी, गुड़, चाय, कॉफी, साबूत मसाले, जैविक तेल, शहद, पिसे हुए मसाले, सूखे मेवे, जैविक बेसन, जैविक चने की दाल, मसूर की दाल, जैविक राजमा, तूअर दाल और साबूत हरा मूंग- आज यह सारे सौ प्रतिशत जैविक वस्तुएं भारत ब्रांड के नाम से उपलब्ध हैं। इसी तरह भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) से पहले जहां बड़े किसानों को ही जोड़ा जाता था, अब ढाई एकड़ वाले किसानों को भी बीज उत्पादन के लिए जोड़ा गया है। आज 20 हजार से अधिक पैक्स के किसान बीज उत्पादन का काम कर रहे हैं। अनाज उगाने से ढाई गुना ज्यादा लाभ बीज की खेती करने में है, जो पहले छोटे किसान नहीं कर पाते थे, लेकिन अब यह संभव हो गया है।



भारत का सहकारी क्षेत्र बहुत ऊर्जावान है और अनेक लोगों की जिंदगी में बदलाव भी ला रहा है। दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है। भारत में आज महिलाओं के नेतृत्व में विकास का दौर है... हम इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में भी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ के अनुसार, सहकारी संस्था “ऐसे लोगों का स्वायत्त संगठन है जो स्वेच्छा से एकजुट होकर अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों को साझा स्वामित्व और लोकतांत्रिक नियंत्रण के माध्यम से पूरा करते हैं।”

सहकारिता: पूंजी के बिना उद्यमिता का मार्ग

पूंजी के बगैर व्यक्ति को उद्यमिता के साथ जोड़ने का एक ही मार्ग है- कोऑपरेटिव सेक्टर। अर्थशास्त्रियों के हिसाब से देश के अर्थतंत्र का मानक है- जीडीपी। जीडीपी देश के अर्थतंत्र का स्वास्थ्य बताने के लिए बड़ा मानक होता है, लेकिन 140 करोड़ की आबादी में जीडीपी के साथ-साथ रोजगार भी बहुत बड़ा माध्यम है। अगले 5 साल में देश में 2 लाख बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत अब तक 35,395 नई सहकारी समितियां बनाई जा चुकी हैं। भूमिहीन और पूंजीहीन व्यक्ति के लिए सहकारिता क्षेत्र से ही समृद्धि का रास्ता खुल रहा है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन चुका है। 2014-15 में दूध का उत्पादन 14 करोड़ टन था जो आज बढ़कर 24 करोड़ टन के पार हो चुका है। अब इसके अंदर चक्रीय व्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी की व्यवस्था की गई है। प्राइवेट में दूध बेचने वालों के पशुओं को भी आहार-टीकाकरण अब कोऑपरेटिव डेयरियां देंगी। उनका गोबर एकत्र कर गैस बनाने का काम करेंगी। जब पशु की मृत्यु होती है तो उसकी चमड़ी और हड्डी भी कोऑपरेटिव के माध्यम से बाजार में ऊंचे दाम किसानों को दिलाने का काम कोऑपरेटिव डेयरियां ही करेंगी। यह परियोजना 10 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से शुरू हो चुका है। सहकारी समितियों के नेतृत्व में 25 दिसंबर 2024 को शुरू हुई श्वेत क्रांति 2.0 के तहत अगले पांच वर्षों में दूध की खरीद को 50% बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

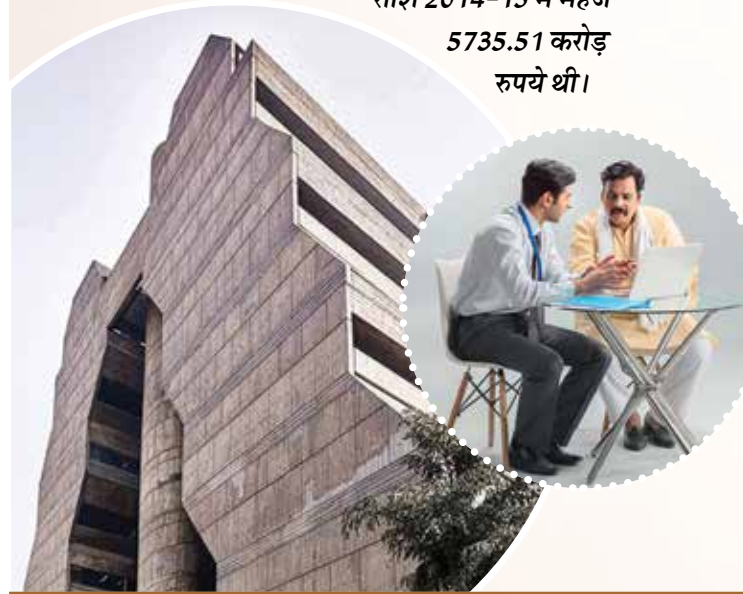
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का बड़ा

भौगोलिक विस्तार

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने अपनी भौगोलिक पहुंच को बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला तो वहीं जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में उप कार्यालय खोले हैं। एनसीडीसी की लोन संवितरण राशि वित्त वर्ष 2020-21 में 24,733 करोड़ रुपये थी जो 2024-25 में बढ़कर 95,183 करोड़ रुपये हो गई है। यह

राशि 2014-15 में महज

5735.51 करोड़ रुपये थी।



सहकारिता मंत्रालय द्वारा पिछले चार वर्षों में पैक्स, डेयरी, मत्स्य, सहकारी बैंक, चीनी सहकारी समितियों और शासन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए की गई 100 से अधिक पहलों में डिजिटल सुधार, नीतिगत परिवर्तन, वित्तीय सहायता और संस्थागत क्षमता निर्माण शामिल हैं।

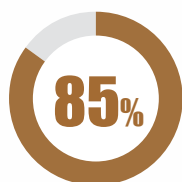
सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर सहकारिता के लिए समावेशी पहल की है। दशकों की उपेक्षा

देश में 30 से अधिक तरह की सहकारी समितियां

देश में बीते कुछ वर्षों में सहकारिता तेजी से बढ़ी है। एक-दो नहीं बल्कि 30 से अधिक श्रेणी में सहकारिता समितियां काम कर रही हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों के नाम और उनकी संख्या यहां बता रहे हैं...

समिति के नाम	समिति की संख्या
पशुधन व कुक्कुट सहकारी	16,735
विपणन सहकारी	9,219
विविध गैर क्रेडिट	30,623
बहुउद्देशीय सहकारी	20,368
प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी	99,359
परिवहन सहकारी	4,174
आदिवासी एससी/एसटी सहकारी	1,516
महिला कल्याण सहकारी	25,067
कृषि एवं संबद्ध	27,143
कृषि प्रसंस्करण सहकारी समिति	22,925
उपभोक्ता सहकारी	21,772
क्रेडिट थ्रिफ्ट सोसायटी	80,331
डेयरी सहकारी	1,43,500
मत्स्य सहकारी	25,894
हथकरघा वस्त्र एवं बुनकर सहकारी	19,613
हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी	1,92,147
श्रम सहकारी	44,859

आज 90 हजार करोड़ रुपये का कारोबार अमूल का है। अमूल में लगभग



उपभोक्ता मूल्य सीधा 36 लाख से अधिक डेयरी किसानों तक पहुंचता है।

और प्रशासनिक कुरीतियों के परिणामस्वरूप अधिकांश प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) आर्थिक रूप से कमजोर और निष्क्रिय हो गई थीं। सरकार ने पैक्स के कार्यक्षेत्र में विस्तार के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने का काम शुरू किया। सहकारिता एक ऐसी व्यवस्था है, जो समाज में आर्थिक रूप से आकांक्षी लोगों को न सिर्फ समृद्ध बनाती है, बल्कि उन्हें अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्यधारा का हिस्सा भी बनाती है। सहकारिता बिना पूंजी या कम पूंजी वाले लोगों को समृद्ध बनाने का एक बहुत बड़ा साधन है। देश

में सहकारिता की एक विस्तृत परंपरा तो रही है, लेकिन आजादी से पहले सहकारिता जिस प्रकार आर्थिक आंदोलन का माध्यम बनी, उसे और भी अधिक ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू हुआ।

नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति

भारत में 24 जुलाई, 2025 को नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 का शुभारंभ किया गया। यह नीति सहकारी क्षेत्र के

... ताकि सहकारिता से बड़े नई पीढ़ी का लगाव

यू तो देश में करीब 32 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में सहकारिता से जुड़े हैं लेकिन भावी पीढ़ी को इससे जोड़कर केंद्र सरकार सहकारिता की मजबूत नींव पर सुव्यवस्थित इमारत बनाना चाहती है। यही वजह है कि सहकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं एनसीईआरटी के परामर्श से नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग (एनसीसीटी) ने सहकारिता पर एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया है। इसका लक्ष्य स्कूली छात्रों को सहकारी समितियों की राष्ट्र निर्माण में भूमिका से अवगत कराना है ताकि वे सहकारिता क्षेत्र को एक करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें। यह विशेष पाठ्यक्रम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम वाले स्कूलों में माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए शुरू किया जाएगा।

- सहकारिता मंत्रालय के निर्देश एवं नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग (एनसीसीटी) के प्रयासों से एनसीईआरटी ने कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में सहकारिता का एक अध्याय शामिल किया है जिससे छात्रों को सहकारिता आंदोलन की मूलभूत जानकारी प्राप्त हो सके।
- वैभवशंकर मितल राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैमनीकॉम), पुणे में शैक्षणिक सत्र 2025 के लिए एआईसीटीई नई दिल्ली से संबद्ध 'पीजीडमएम-सहकारिता' का नया पाठ्यक्रम शुरू करने की पहल की गई है। इसमें 30 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।

सहकारिता प्रशासन, शिक्षा और शोध को नई दिशा देगा टीएसयू

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (टीएसयू) न सिर्फ ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा, बल्कि पारदर्शी, पेशेवर और समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत में सहकारिता शिक्षा, शोध और प्रशासन को नई दिशा देगा। यह सहकारी शिक्षा का शीर्ष संस्थान होगा। तीन स्तर की पाठ्यक्रम प्रणाली तैयार की गई है। संचालन के स्तर पर 10वीं तक पढ़ाई करने वालों को आवश्यक प्रारंभिक ज्ञान और तकनीकी दक्षता के कोर्स ऑफर किए जाएंगे। पर्यवेक्षक के स्तर पर डिप्लोमा प्रोग्राम संचालित किए जाएंगे, जो सहकारी संस्थाओं के मध्य प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए उपयुक्त होंगे। वहीं प्रबंधकीय स्तर पर डिग्री और पीएचडी कार्यक्रमों की पेशकश की जाएगी। यह विश्वविद्यालय अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित करेगा ताकि दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले सहकारी कार्यकर्ताओं तक गुणवत्ता-युक्त शिक्षा पहुंचाई जा सके।

- टीएसयू विभिन्न राज्यों में सेक्टर-विशिष्ट शैक्षिक और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करेगा जिसके तहत गुजरात में डेयरी सहकारिता, केरल में मत्स्य सहकारिता, महाराष्ट्र में सहकारी वित्त और उत्तर प्रदेश-बिहार में महिला सहकारिता से संबंधित संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य शामिल है।
- पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होगा, जिसमें बहु-विषयक अध्ययन होंगे। इस विश्वविद्यालय का डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर साल 8 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। यह विश्वविद्यालय नए वर्ष 2026 में पूरी तरह से काम शुरू कर देगा।



व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए एक रोडमैप और व्यापक ढांचा प्रदान करती है। नीति का मिशन अगले 10 वर्षों में 16 उद्देश्यों को प्राप्त करना है जिन्हें छह रणनीतिक मिशन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अगर राष्ट्रीय सहकारिता नीति- 2025 के उद्देश्य को एक वाक्य में कहा जाए तो यह 'सहकार से समृद्धि' के माध्यम से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है।

सहकारिता विश्वविद्यालय से नई पीढ़ी का निर्माण

जेनरेशन यानी पीढ़ीगत सहकार का विकास के मंत्र के साथ त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात में की गई है। इसके लिए संसद ने मार्च 2025 में कानून बनाया है लेकिन इसका कार्यक्षेत्र समूचा भारत होगा। इससे प्रशिक्षित संसाधन सहकारिता क्षेत्र को मिलेंगे। केंद्र सरकार ने करीब साढ़े 4 वर्ष



अमित शाह: जिनके दिल के करीब रहा 'सहकार से समृद्धि' का मूलमंत्र

गुजरात की राजनीति में सक्रिय रहने के दौरान ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का रुझान सहकारिता आंदोलन के प्रति बन गया था। वह 18 वर्ष की उम्र से ही सहकारिता से जुड़े हुए हैं और इसकी खूबियों और कमजोरियों को बेहद करीब से अनुभव किया है। जब वह 2001 में राजनैतिक संगठन के सहकारिता प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक थे तभी सहकारिता आंदोलन के प्रति उनकी गहरी अंतर्दृष्टि राष्ट्रीय स्तर पर सामने आने लगी थी। उन्हें दो मृतप्राय बैंकों - अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक और अहमदाबाद के माधवपुरा बैंक के पुनरुद्धार का श्रेय भी दिया जाता है। देश में भी सहकारिता में ढेर सारे परिवर्तन करने की जरूरत थी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सहकारिता मंत्रालय का गठन किया तो उसकी जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई। देश के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री के रूप में बहुत ही कम समय में उन्होंने कई नई योजना, नीतिगत पहल और सुधारात्मक कदमों से प्रशासनिक और नीतिगत स्तर पर इस क्षेत्र का कार्यालय कर दिया है। इसके लिए संसद में विधेयक पारित कर, इस क्षेत्र को राष्ट्रीय विमर्श की मुख्यधारा में ला दिया है। उनके प्रयास और प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि 'सहकार से समृद्धि' भारत के आर्थिक नियोजन और प्रगति में आज एक चर्चित शब्द बन गया है। सहकारिता का क्षेत्र उनके दिल के कितना करीब है और राष्ट्र-समाज के निर्माण में महत्व रखता है, वह उनके इस कथन से स्पष्ट होता है, "देश का गृहमंत्री होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सरदार पटेल साहब भी गृहमंत्री थे। लेकिन जिस दिन मुझे सहकारिता मंत्री बनाया गया, मैं मानता हूँ कि उस दिन गृह मंत्रालय से भी बड़ा डिपार्टमेंट मुझे मिल गया। यह ऐसा मंत्रालय है जो देश के गरीबों, किसानों, गावों और पशुओं के लिए काम करता है।"

में जो कोऑपरेटिव का विकास किया है, उसके अनुभव के आधार पर सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इससे सहकारिता में नौकरी में भाई-भतीजावाद नहीं होगा, बल्कि सहकारिता क्षेत्र में डिग्री अब महत्वपूर्ण आधार होगा। डिग्री-डिप्लोमा वाले और मेरिट वालों को ही नौकरी मिलेगी। इससे एक नई सहकारिता संस्कृति की शुरुआत होगी। इस सहकारिता विश्वविद्यालय में प्रति वर्ष 8 लाख लोगों को शिक्षण देने की व्यवस्था होगी। देश भर में इसके संबद्ध कॉलेज और स्कूल खुलेंगे। इसके अंदर 10वीं-12वीं, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि के कोर्स भी होंगे।

प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ काम मिले, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे यह केंद्र सरकार की सोच है। अच्छे जीवन का स्वप्न कोऑपरेटिव के बिना पूरी नहीं हो सकता। इसके महत्व को समझते हुए केंद्र और राज्य ने मिलकर भारत में सहकारिता आंदोलन के नए युग की शुरुआत कर दी है। सहकारिता आंदोलन भारत के ग्रामीण समाज की प्रगति सुनिश्चित करते हुए एक नई सामाजिक पूंजी की अवधारणा खड़ी कर रहा है। सहकारिता की सफलता चार चीजों- संकल्प शक्ति, साफ नीयत, परिश्रम और संघ भाव पर निर्भर करती है। इसी भाव से आम नागरिक के स्वप्न को पूरा करने का सहकारिता जरिया बन रही है। ■

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह

आदिवासी कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता

आज देश के पास 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र की ताकत है। इस मंत्र ने बीते वर्षों में करोड़ों लोगों का जीवन बदला है, देश की एकता को मजबूती दी है और दशकों से उपेक्षित जनजातीय समाज को मुख्यधारा से भी जोड़ा है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को मजबूत करने की शपथ लेने का आह्वान किया ताकि न विकास में कोई पीछे रहे और न कोई पीछे छूटे...

भारत के सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज की जब-जब बात आई तो आदिवासी समाज सबसे आगे खड़ा हुआ। आदिवासी समाज से निकले कितने ही नायक-नायिकाओं ने आजादी की मशाल को आगे बढ़ाया। तिलका मांझी, रानी गाईदिनल्यू, सिद्धू-कान्हो, भैरव मुर्मू, बुद्धो भगत, जनजातीय समाज को प्रेरणा देने वाले अल्लूरी सीताराम राजू, मध्यप्रदेश के तांत्या भील, छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह, झारखंड के तेलंगा खड़िया, असम के रूपचंद कोंवर और ओडिशा के लक्ष्मण नायक ने आजादी के लिए असीम त्याग और संघर्ष किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जीवन भर अंग्रेजों को चैन से बैठने नहीं दिया। आदिवासी समाज ने अनगिनत क्रांतियां कीं, आजादी के लिए अपना लहू बहाया। गुजरात के डेडियापाड़ा में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में आदिवासी समुदाय के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में द्राइबल समाज के योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा है।

किसी भी समाज की प्रगति के लिए लोकतंत्र में उसकी सही भागीदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। इसीलिए, हमारा ध्येय है, जनजातीय समाज के हमारे भाई-बहन देश के बड़े पदों पर भी पहुंचें, देश का नेतृत्व करें। आप देखिए, आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला हैं।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना सुचारु रूप से बढ़ रही आगे

गुजरात के सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का पीएम मोदी ने दौरा किया और मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की टीम से बातचीत की और गति तथा समय सारिणी के लक्ष्यों के पालन सहित परियोजना की प्रगति के बारे में जानकारी ली। कर्मियों ने बताया कि परियोजना बिना किसी कठिनाई के सुचारु रूप से आगे बढ़ रही है।

परियोजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास से विकास को मिलेगी और गति

- गुजरात के डेडियापाड़ा जनजातीय समुदायों के उत्थान और क्षेत्र के ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के उद्देश्य से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास।
- एक लाख घरों में गृह प्रवेश : प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेएजीयूए) के तहत निर्मित।
- लगभग 1,900 करोड़ रुपये की लागत से जनजातीय छात्रों को समर्पित 42 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) का उद्घाटन।
- समुदाय-आधारित कार्यकलापों के हब के रूप में कार्य करने वाले 228 बहुउद्देश्यीय केंद्र, असम मेडिकल कॉलेज, डिब्रूगढ़ में सक्षमता केंद्र और मणिपुर के इंफाल में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण हेतु जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) भवन का उद्घाटन।
- जनजातीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधार के लिए गुजरात के 14 जनजातीय जिलों के लिए 250 बसों को इंडी।
- जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिए 748 किलोमीटर नई सड़कों और सामुदायिक केंद्रों के रूप में काम करने के लिए डीए-जगुआके अंतर्गत 14 जनजातीय बहु-विपणन केंद्र की (टीएमएमसी) आधारशिला।

2,320

करोड़ रुपये से अधिक

की लागत से बनने वाले 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला।

आदिवासी युवाओं को जब अवसर मिलता है तो वह हर क्षेत्र में बुलंदी को छूने की ताकत रखते हैं। हिम्मत, मेहनत और काबिलियत, उन्हें परंपरा और विरासत में मिले हुए हैं। खेल जगत के उदाहरण से समझ सकते हैं कि आदिवासी बेटे-बेटियों ने दुनिया में तिरंगे की शान बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान दिया। केंद्र सरकार आदिवासी बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 5-6 वर्षों में ही केंद्र सरकार ने देश में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 18 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है। छात्राओं के लिए स्कूल में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। नतीजा यह है कि इन स्कूलों में एडमिशन लेने वाले ट्राइबल बच्चों की संख्या में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

देवमोगरा माता मंदिर में पूजा-अर्चना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देवमोगरा माता मंदिर का दौरा किया। यहां उन्होंने देवमोगरा माता की पूजा-अर्चना की और सभी नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और प्रगति के लिए आशीर्वाद मांगा। पीएम मोदी ने इस अनुभव को पवित्र बताया और देश भर के लोगों से मंदिर में आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आग्रह किया।

झारखंड के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं

झारखंड के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी। झारखंड एक गौरवशाली भूमि है जो जीवंत आदिवासी संस्कृति से समृद्ध है। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि इस पवित्र भूमि का इतिहास साहस, संघर्ष और गरिमा की प्रेरक कहानियों से भरा पड़ा है। ■



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



सहायता से स्वालंबन तक दिव्यांगों का बढ़ता आत्मविश्वास

अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस उस अटूट आत्मबल और सकल्प का उत्सव है जो सीमाओं को नई संभावनाओं में बदल देता है। केंद्र सरकार की नीतियों ने इन संभावनाओं एवं उम्मीदों को और बढ़ाया है। आइए समझते हैं कि कैसे पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के जीवन को गरिमापूर्ण और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए हैं प्रयास...

हर व्यक्ति के भीतर कुछ कर दिखाने की शक्ति होती है। बस जरूरत होती है उसे अवसर देने की और उसमें विश्वास जताने की। यह कहानी है दोनों बाजू न होने के बावजूद छाती के सहारे दांतों और पैर से धनुष-बाण चलाने वाली जम्मू-कश्मीर की तीरंदाज 18 वर्षीय शीतल देवी की। शीतल जन्म से ही दुर्लभ बीमारी फोकोमेलिया से पीड़ित थीं लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सरकार ने भी कदम-कदम पर साथ दिया। शीतल ने भारतीय सेना के एक युवा कार्यक्रम के लिए नामांकन कराया और यहीं से उनके खेल करियर की नींव पड़ी। हांगझोउ एशियाई पैरा खेलों में तीरंदाजी की और महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। देश में दिव्यांगजनों की ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो प्रेरणा देती हैं और यह सब केंद्र सरकार की नीतियों, निर्णयों और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की पहल से संभव हो पाया है।



इन पहलों से सशक्त हो रहे दिव्यांगजन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने पूरे भारत में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए 16 पहल शुरू की है, इनमें से एक सुगम्य भारत अभियान जिसकी शुरुआत अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस (3 दिसंबर) 2015 को हुई। दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता के उद्देश्य से शुरू इस राष्ट्रव्यापी पहल के 10 वर्ष हो रहे हैं पूरे, जिसने बढ़ाई है सुगम्यता...

1. सुगम्य भारत अभियान
2. सुगम्य भारत यात्रा
3. पहुंच के रास्ते
4. हाई-पावर चश्मे
5. दिव्यशाई-कॉफी टेबल बुक
6. कदम घुटने का जोड़
7. जागरूकता सृजन और प्रचार पोर्टल
8. सुलभ कहानी पुस्तकें
9. मानक भारती बेल कोड
10. बेल बुक्स पोर्टल
11. इंपोसिस बीपीएम के साथ समझौता ज्ञापन
12. रोजगार कौशल पुस्तक
13. इंपोसिस स्पिंगबोर्ड कौशल कार्यक्रम
14. श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए गूगल एक्सटेंशन
15. ई-सानिध्य पोर्टल
16. एनआईडीपीआईडी, सिकंदराबाद द्वारा कंप्यूटर-आधारित भारतीय बुद्धि परीक्षण।



सुगम्य भारत अभियान ने बढ़ाई हर स्तर पर सुगम्यता

153

अंतरराष्ट्रीय हवाई और घरेलू हवाई अड्डों पर व्हीलचेयर, स्वचालित सीढ़ी (रैप), शौचालय, स्पर्श योग्य पेविंग और फर्श एवं लिफ्ट के साथ-साथ पार्किंग की सुविधा उपलब्ध।

42,000

से अधिक बस आंशिक तरीके से और 8,695 बस पूरी तरह सुगम्य।



709

रेलवे स्टेशनों पर रैप, शौचालय, लिफ्ट, हेल्प डेस्क, पार्किंग, पेयजल सुविधा।

3,120

बस अड्डा दिव्यांगजन फ्रेडली।

दिव्यांग बच्चों की हो बेहतर पढ़ाई...

- कक्षा 1 से 6 तक की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित। कक्षा 1 से 3 की पाठ्यपुस्तक भी आईएसएल में परिवर्तित।
- भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के सहयोग से माध्यमिक स्तर पर भाषा विषय के रूप में आईएसएल के लिए पाठ्यक्रम विकसित किया।
- 10 हजार से ज्यादा शब्दों का आईएसएल शब्दकोश विकसित।

1.26 करोड़

के करीब विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र बनाए गए हैं।



दिव्यांगजनों का जीवन बना आसान

- एक लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना में दिव्यांगता की कुछ श्रेणी में 1 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाता है।
- 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2021 के तहत 14 निर्दिष्ट उत्कृष्टता केंद्रों पर 63 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता।

2.68 करोड़

दिव्यांगजन संख्या, जो कुल आबादी का 2.21% है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार।

फैसले और कार्य जो दिव्यांगजनों को बना रहे हैं सशक्त

- पिछले 11 वर्षों के दौरान 31.16 लाख दिव्यांग को 2,415 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सहायक उपकरण और सहायता।
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से शिविर का आयोजन, इस दौरान बने 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड।
- 2014 के पहले सिर्फ 7 लाख लोगों को कृत्रिम अंग और यंत्र दिए थे। 2014 से अब तक 31 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग दिए गए।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

- मान्यता प्राप्त दिव्यांगता श्रेणी की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगों को मिले लाभ।
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया।
- उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी किया गया।



न्याय में सुगमता से जीवन और कारोबार की सुगमता

जब न्याय हर व्यक्ति की पहुंच में होता है, सामाजिक और वित्तीय पृष्ठभूमि की बाधा के बिना हर व्यक्ति तक पहुंचता है, तभी वो सामाजिक न्याय की नींव बनता है। न्याय के इसी मूल अधिकार को सशक्त एवं सरल बनाने के लिए 8 नवंबर को 'कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने' पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन...

भारत की कानून व्यवस्था अब दंड व्यवस्था के साथ नहीं चलती, बल्कि न्याय पर केंद्रित है। न्याय हर व्यक्ति का मूल अधिकार है, इस न्याय तक हर व्यक्ति की आसानी से पहुंच होनी चाहिए। न्याय तक सुलभ पहुंच और कानूनी सहायता से 'ईज ऑफ जस्टिस' सुनिश्चित करने की दिशा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस साल 'नाल्सा' के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन तीन दशक में 'नाल्सा' ने न्यायपालिका को देश के गरीब नागरिकों तक जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर तालुका स्तर तक, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, न्यायपालिका और नागरिक के बीच सेतु का काम करती हैं। आज लोक अदालतों और प्री-लिटिगेशन

सेटलमेंट्स के माध्यम से, लाखों विवाद जल्दी सौहार्दपूर्ण और कम खर्च में सुलझाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम शुरू किया, उससे महज तीन वर्ष में, लगभग 8 लाख आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया है। सरकार के इन प्रयासों ने देश के गरीब-दलित-पीड़ित-शोषित-वंचित के लिए ईज ऑफ जस्टिस सुनिश्चित किया है।

बीते 11 वर्षों के दौरान देश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लीविंग' के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। 40 हजार से अधिक अनावश्यक अनुपालनों को हटाया है तो जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से 3,400 से ज्यादा कानूनी धाराओं को गैर आपराधिक बनाया है। साथ ही, 1,500 से अधिक अप्रासंगिक और पुराने कानून रद्द किए गए हैं। दशकों से चले आ रहे पुराने कानूनों को

सामुदायिक मध्यस्थता योजना लॉन्च...

न्याय तक पहुंच का जन आंदोलन

कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के तंत्र की मजबूती और कानूनी सेवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विवाद को आपसी सहमति और शांति से सुलझाने के लिए सामुदायिक मध्यस्थता योजना के कम्युनिटी मीडिएशन ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया। यह लोगों तक न्याय और सामुदायिक समाधान पहुंचाएगी। पीएम मोदी कहते हैं कि नए मॉड्यूल से भारतीय परंपरा की उस प्राचीन विद्या को पुनर्जीवित कर रहे हैं, जिसमें संवाद और सहमति के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता था। ग्राम पंचायतों से लेकर गांव के बुजुर्गों तक, मध्यस्थता हमेशा से देश की सभ्यता का हिस्सा रही है। नया मध्यस्थता अधिनियम इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है। सामुदायिक मध्यस्थता के लिए ऐसे संसाधन तैयार होंगे, जो विवादों को सुलझाने, सौहार्द बनाए रखने और मुकदमेबाजी को कम करने में मदद करेंगे।

18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद शुरू

न्याय की भाषा वही हो, जो न्याय पाने वाले को समझ आए। जब कानून को ड्राफ्ट किया जाता है, तब इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब लोग कानून को अपनी भाषा में समझते हैं, तो इससे बेहतर अनुपालन होता है। मुकदमेबाजी कम होती है। न्यायालय के फैसले और कानूनी दस्तावेज स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने उच्चतम न्यायालय के 80 हजार से अधिक निर्णयों को 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने वाली पहल की सराहना की। साथ ही, कहा कि यह प्रयास उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर भी होनी चाहिए।



एक गरीब व्यक्ति तब तक न्याय नहीं पा सकता, जब तक उसे अपने अधिकारों का ज्ञान न हो, वह कानून को न समझे और सिस्टम की जटिलता से डर महसूस करता रहे। इसलिए कमजोर वर्गों, महिलाओं और बुजुर्गों में लीगल अवेयरनेस को बढ़ाना, यह हमारी प्राथमिकता है। हमारे युवा, खासकर कानून के छात्र, इसमें बदलाव लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

आपसी समझौते से सुलझाए 8 लाख से अधिक मामले

- मध्यस्थता के माध्यम से 8 लाख 61 हजार मामले आपसी समझौते से सुलझाने के साथ ही अभी तक 1.6 करोड़ नागरिकों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई है।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) ने बीते एक दशक में अपना नेटवर्क 37 राज्य प्राधिकरण, 707 जिला प्राधिकरण और 2,440 कानून समिति तक फैलाया है।
- नाल्सा ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुंच योजना, 2025 और वीर परिवार सहायता योजना के जरिए न्याय को सरल और सुलभ बनाने का प्रयास किया है।
- नाल्सा ने नवाचार और डिजिटलीकरण को अपनाते हुए न्याय तक पहुंच को आसान बनाया है।
- स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से देश भर में 13 लाख 11 हजार से अधिक महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामले सुलझाए गए हैं। साथ ही 2,354 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा पीड़ितों को दिलावाया है।



अब भारतीय न्याय संहिता से बदला गया है। पीएम मोदी ने सम्मेलन में यह स्पष्ट किया कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लीविंग' तभी संभव हैं, जब 'ईज ऑफ जस्टिस' भी सुनिश्चित हो। पिछले कुछ वर्षों में, 'ईज ऑफ जस्टिस' को बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। टेक्नोलॉजी आज समावेशन और सशक्तीकरण का माध्यम बन रही है। जस्टिस डिलिवरी में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट ने दिखाया

है कि कैसे टेक्नोलॉजी न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक और मानवीय बना सकती है। ई-फाइलिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक समन सर्विस तक, वर्चुअल हियरिंग से लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ आसान कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के बजट को बढ़ाकर 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा किया गया है। ■



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

प्रगति के पथ पर... वंदे भारत की रफ्तार

दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। भारत भी उसी दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में भारत के आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को वाराणसी से चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना...



कल्पना कीजिए कोई इलाका है। लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, स्टेशन नहीं है। जैसे ही वहां पटरी बिछ जाती है, स्टेशन बन जाता है, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। उसी तरह किसी गांव में सालों तक पक्की सड़क नहीं है। जैसे ही वहां एक अच्छा रास्ता बन जाता है तो किसानों का माल वहां से बाजार जाना शुरू हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बड़े-बड़े ब्रिज, हाईवेज तक ही सीमित नहीं होता है बल्कि जब ऐसी सुविधाएं विकसित होती हैं तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। लोगों को इस तरह का अनुभव कस्बा, छोटे नगर और पूरे देश में भी देखने को मिलता है। पिछले 11 वर्षों में देश में कई नए हवाई अड्डे बने और वंदे भारत ट्रेनें भी चलने लगी हैं जिससे विकास को नए पंख लगे हैं। वाराणसी से चार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सारी बातें विकास के साथ जुड़ चुकी हैं। आज भारत भी बहुत तेज गति से विकास के इसी रास्ते पर चल रहा है। चार नई वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने के साथ ही, अब देश में 164 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है।

भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देवदर्शन का मार्ग नहीं हैं बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा हैं। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, ऐसे अनगिनत तीर्थक्षेत्र आध्यात्मिक धारा के केंद्र हैं। आज जब ये पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं तो इससे भारत की संस्कृति, आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम पूरा हो रहा है। यह भारत की विरासत के शहरों को, देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम है। पीएम

कई विशेषताओं से सुसज्जित वंदे भारत एक्सप्रेस

- 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में 140 सेकंड का समय।
- आनंदपूर्ण, आरामदायक, शांत और सुरक्षित सफर।
- प्रत्येक कोच में इंफोटेनमेंट सिस्टम।
- बेहतर हीट वेंटिलेशन और समान वितरण के लिए एयर कंडीशनिंग इकाई।
- टच-फ्री सुविधाओं वाले बायो वैक्यूम शौचालय।
- सभी कोच में अग्निशमन सुरक्षा के बेहतर उपाय।
- कवच (ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली) से लैस।
- दिव्यांगजनों के लिए विशेष शौचालयों की व्यवस्था एवं ब्रेल लिपि में सूचनाएं।
- सभी कोच में आपातकालीन लाइटिंग, इमरजेंसी विंडो और टॉक बैंक यूनिट।

पर्यटन को बढ़ावा आरामदायक यात्रा

- क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा।
- यात्रा समय में कमी।
- यात्रियों को आधुनिक, आरामदायक और कुशल यात्रा का विकल्प।
- क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा।

♥♥ आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों, भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही हैं। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई गई ट्रेन है। जिस पर हर भारतीय को गर्व है। ♥♥

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

वंदे भारत एक्सप्रेस से आसान और तेज हुआ सफर...

- बनारस-खजुराहो वंदे भारत : इस मार्ग पर सीधा संपर्क स्थापित। वर्तमान में चल रही ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत।
- लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत : लगभग 7 घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी। इससे यात्रा समय लगभग 1 घंटा बचेगा।
- फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत : इस रूट पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। मात्र 6 घंटे 40 मिनट में यात्रा पूरी करेगी।
- एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत : यात्रा के समय को 2 घंटे से अधिक कम कर देगी। इससे यात्रा 8 घंटे 40 मिनट में पूरी होगी।

4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नए गंतव्य के लिए रवाना



मोदी ने कहा कि इन यात्राओं का एक आर्थिक पहलू भी होता है। बीते 11 वर्षों में, उत्तर प्रदेश में हुए विकास कार्यों ने तीर्थान को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपये

का लाभ पहुंचाया है। इन्होंने होटल, व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों, स्थानीय कलाकारों, नाव चलाने वालों को निरंतर कमाई का अवसर दिया है। इसके कारण बनारस के सैकड़ों नौजवान, अब ट्रांसपोर्ट से लेकर बनारसी साड़ियों तक, हर एक चीज में नए-नए व्यापार शुरू कर रहे हैं। इन सबकी वजह से उत्तर प्रदेश के साथ-साथ काशी में समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं। ■



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



‘देवभूमि उत्तराखंड’ भारत के आध्यात्मिक जीवन की धड़कन

अपनी स्थापना के बाद से बीते 25 वर्षों में उत्तराखंड ने पहाड़ की सीमाओं से आगे बढ़कर इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, कौशल विकास और व्यवसाय के साथ समृद्ध आध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत को भी नए आयाम दिए हैं। तभी उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि राज्य तय कर ले तो आने वाले वर्षों में यह ‘विश्व की आध्यात्मिक राजधानी’ के रूप में हो सकता है स्थापित...

उत्तराखंड के इतिहास में 9 नवंबर की तारीख एक लंबे और समर्पित संघर्ष के परिणाम का दिन है। उत्तराखंड के लोगों ने जो स्वप्न देखा था उसे 25 वर्ष पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पूरा किया था। आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है, उसे देखकर इस राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले लोग बेहद प्रसन्न होंगे। राज्य के सामर्थ्य को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य की प्रतिबद्धता पर संतोष व्यक्त करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के स्थापना की रजत जयंती (9 नवंबर) समारोह में राज्य के विकास के लिए 8,140 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

प्रदेश की विकास यात्रा को गति देने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी पीएम मोदी ने समारोह में किया। इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। जमरानी और सोंग बांध परियोजना देहरादून और

हलद्वानी में पेयजल की समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए वर्तमान में दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजना पर काम चल रहा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम प्रगति पर है और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। गौरीकुंड-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। इन परियोजनाओं से उत्तराखंड के विकास को और गति मिलेगी।

25 वर्ष में विकास ने पकड़ी तेज रफ्तार...

प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य और यहां के लोगों के साथ गहरे भावनात्मक जुड़ाव और अपनी आध्यात्मिक यात्राओं का जिक्र करते हुए कहा कि पहाड़ों में रहने वाले भाई-बहनों के संघर्ष, कड़ी मेहनत और उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया है। 25 वर्ष पहले जब राज्य का गठन हुआ था उस समय यहां अपार चुनौतियां थीं। राज्य के पास संसाधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील...

- उत्तराखंड के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में योग केंद्र, आयुर्वेद केंद्र और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों का एक संपूर्ण पैकेज हो। यह विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा।
- उत्तराखंड के हर जीवंत गांव को एक छोटा पर्यटन केंद्र बनाया जाना चाहिए, जहां होमस्टे, स्थानीय व्यंजनों और संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके।
- नंदा देवी, जौलजीवी, बागेश्वर का उत्तरायणी, देवीधुरा, श्रावणी और मक्खन महोत्सव जैसे स्थानीय त्योहारों और परंपराओं को विश्व मानचित्र पर लाने के लिए 'एक जिला एक महोत्सव' जैसे अभियान चलाए जाएं।
- उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिलों में फलों की खेती की संभावनाओं को देखते हुए इन्हें बागवानी केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।
- 'वेड इन इंडिया पहल' के लिए उत्तराखंड को व्यापक स्तर पर सुविधाएं विकसित करनी चाहिए और पांच से सात प्रमुख स्थलों की पहचान कर उनका विकास करना चाहिए।



इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को मिलेगी गति...

पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास सहित कई अन्य क्षेत्रों में पीएम मोदी ने 7,210 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और 930 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

28,000

से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सीधे उनके बैंक खातों में 62 करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजी गई।

उद्घाटन

23

क्षेत्रों के लिए अमृत योजना के अंतर्गत देहरादून जलापूर्ति कवरेज, पिथौरागढ़ जिले

में विद्युत सब-स्टेशन, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र और नैनीताल के हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटेर्फ हॉकी मैदान।

शिलान्यास

सौंठ बांध पेयजल परियोजना, जो देहरादून को 150 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) पेयजल उपलब्ध कराएगी और नैनीताल में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय और नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र।

सीमित थे, राज्य का बजट और आय के स्रोत कम थे। अधिकांश जरूरतें केंद्रीय सहायता से पूरी होती थीं। अब स्थिति बदल गई है। 25 वर्ष पहले जहां राज्य का बजट 4 हजार करोड़ रुपये था वहीं अब बजट एक लाख करोड़ रुपये हो गया है। राज्य में बिजली उत्पादन में चार गुना की बढ़ोतरी हुई है, सड़कों की लंबाई दोगुनी हो गई है। पहले छह महीने में केवल चार हजार हवाई यात्री यहां आते थे जबकि अब एक दिन में चार हजार से ज्यादा लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। राज्य में बुनियादी ढांचे के

साथ-साथ शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, बिजली और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में सफलता की कई प्रेरणादायक कहानियां हैं। पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड में इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या दस गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। पहले यहां केवल एक मेडिकल कॉलेज था, जबकि आज 10 हैं। टीकाकरण कवरेज 25 प्रतिशत से भी कम थी लेकिन अब उत्तराखंड का लगभग हर गांव टीकाकरण कवरेज के दायरे में आता है। ■



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



हर तरह की आपदा में सुरक्षित न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट

परमाणु और नाभिकीय (न्यूक्लियर) संयंत्र का नाम आते ही लोगों के मन में उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता जागृत हो जाती है, लेकिन भारत में इन प्लांट और आसपास के क्षेत्र को विशेष मानकों के साथ सुरक्षित और संरक्षित किया गया है। रिक्टर पैमाने पर 8.6 से 9.0 की तीव्रता के भूकंप भी आए तो देश के परमाणु संयंत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आबादी की सुरक्षा-संरक्षा की भी है विशेष प्रणाली...

भारत की न्यूक्लियर एनर्जी की क्षमता अभी 24 रिएक्टरों से 8,780 मेगावाट है जबकि 13,600 मेगावाट क्षमता के लिए काम अलग-अलग चरणों में चल रहा है। इसमें से 2,000 मेगावाट क्षमता रूसी संघ और 320 मेगावाट क्षमता अमेरिका के सहयोग से स्थापित की गई है। देश में कुल विद्युत उत्पादन में न्यूक्लियर एनर्जी की हिस्सेदारी 3% है। देश के लिए महत्वपूर्ण इन संयंत्रों के विस्तार के लिए भारत सरकार नए मिशन पर काम कर रही है तो इनकी सुरक्षा और संरक्षा का भी लगातार मूल्यांकन करती है। बीते दिनों परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री की तरफ से संसद में दिए गए एक जवाब में यह बात साफ की गई कि विश्व में कभी भी न्यूक्लियर संरक्षा से संबंधित कोई बड़ी घटना होती है तो उस हिसाब से जांच के लिए संरक्षा पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

वैश्विक स्तर पर घटनाओं में रूस और जापान में आए भूकंप एवं 2011 में फुकुशिमा दाइची दुर्घटना के बाद भूकंप, बाढ़ और बड़ी प्राकृतिक घटनाओं का सामना करने के लिए भारतीय विद्युत संयंत्रों की क्षमता और सीमा का परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद

लगभग 56,581 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट ने किया है।

ने मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन में यह बात साफ हुई कि भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय से यदि रिक्टर पैमाने पर 9.0 तीव्रता तक के भूकंप भी आए तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, दिशा निर्देशों के अनुरूप समय-समय पर संरक्षा का मूल्यांकन किया जाता है। यह भी बताया गया कि तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक न्यूक्लियर पावर प्लांट को भूकंप, सुनामी, तूफानी लहरों और बाढ़ से संबंधित तकनीकी मानदंडों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। इतना ही नहीं कर्मियों को ऐसी कठिन परिस्थिति में की जाने वाली कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् ने चालू संयंत्रों

परमाणु आपातकाल प्रबंधन का मजबूत ढांचा

भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट (एनपीपी) के डिजाइन में संरक्षा की अवधारणा, विशेषताएं और प्रणालियां शामिल की जाती हैं। निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने से यहां गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका बहुत कम होती है। परमाणु आपातकाल के प्रबंधन का एक बहुत ही मजबूत ढांचा है। परमाणु ऊर्जा स्थलों के आसपास रहने वाली आबादी की सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली तय है जिनमें ये बिंदु हैं शामिल...

- न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थल का निर्धारण, निर्माण, ऑपरेशन सभी परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् की तरफ से निर्धारित कड़े नियामक और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।
- आपातकाल स्थिति में रेडियोसक्रिय उत्सर्जन के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के लिए एनपीपी के आसपास योजना क्षेत्र की पहचान की जाती है। यह तत्काल एहतियाती और तत्काल संरक्षक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए है।
- जिस जिले या राज्य में न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, उनके पास जिला व राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन योजना है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से बनाई जाती है।
- प्रत्येक न्यूक्लियर सर्विस के चारों ओर 1.5 किलोमीटर वर्जित क्षेत्र, 5 किलोमीटर तक निष्क्रिय क्षेत्र और 16 किलोमीटर तक आपातकालीन योजना क्षेत्र होता है।

66

वर्ष 2047 तक हम देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना से अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने 2025 में ही 50% स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य हासिल कर लिया, जो 2030 के निर्धारित लक्ष्य से पांच वर्ष पहले है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

के बीते 2 वर्ष के दौरान 86 निरीक्षण किए। इन निरीक्षण में रेडियो सक्रिय अपशिष्ट प्रबंधन, आपातकालीन तैयारी योजना को लेकर कोई खामी नहीं पाई गई।

न्यूक्लियर विद्युत उत्पादन में भागीदार बनेंगे निजी क्षेत्र

न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी उत्पादन की योजना बनाई गई है। इसके लिए इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदार को भी अनुमति दी गई है। इस संबंध में परमाणु ऊर्जा विभाग ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण, स्वामित्व, ऑपरेशन, न्यूक्लियर संरक्षा और सुरक्षा एवं अपशिष्ट प्रबंधन के पहलुओं पर विचार करने के लिए एक कार्यदल गठित किया है। वहीं न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में विदेशी भागीदार सरकार की मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार रखने की व्यवस्था की गई है।

नेट जीरो में सहायक बनेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट

बीते 5 वर्षों के दौरान 2,100 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता को ग्रिड से जोड़ा गया है। इस अवधि में न्यूक्लियर एनर्जी संयंत्रों से लगभग 241 अरब यूनिट स्वच्छ बिजली उत्पादित की गई है। इससे पर्यावरण में 20.7 करोड़ टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) के समतुल्य उत्सर्जन कम हुआ है। लंबी अवधि में, न्यूक्लियर एनर्जी से स्वच्छ बिजली उपलब्धता बढ़ेगी जिससे न सिर्फ देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी। ■

आईसीसी महिला विश्व कप चैंपियन से पीएम मोदी की बातचीत

नए भारत की खेल भावना का प्रतीक

अंतरराष्ट्रीय मंच से लेकर खेल के मैदान तक आज भारत का परचम हर तरफ लहरा रहा है। इसी परचम में एक और सुनहरा अध्याय तब जुड़ा जब देश की बेटियों ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीतकर भारत के गौरव को आसमान पर पहुंचा दिया। विश्व कप विजेता की इन्हीं महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उनके जज्बे, मेहनत और साहस को सराहा...

खेल के मैदान में जब भारतीय खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तो उनके पीछे पूरा देश साथ खड़ा रहता है। स्टेडियम में भारत का उत्साह गूंजता है और हर जीत में देशवासी का अभिमान बसता है। यही कारण है कि 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने से लेकर उनका उत्साह बढ़ाने तक का काम निरंतर कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा से खेल अब सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब यह नए भारत का आंदोलन बन चुका है। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन की इसी कड़ी में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 चैंपियन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर 6 नवंबर

को मुलाकात में कहा कि सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है। क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है और क्रिकेट में थोड़ा सा भी इधर-उधर हो गया तो पूरा भारत हिल जाता है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोटिवेशन आया काम
वर्ष 2017 में फाइनल मैच हारने के बाद जब महिला क्रिकेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली थीं उस पल को याद करते हुए कहा कि उस समय प्रधानमंत्री से मिला मोटिवेशन आज तक काम आ रहा है।





भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात

आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों ने 6 नवंबर, 2025 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने महिला क्रिकेट टीम की प्रत्येक सदस्य को बधाई दी और कहा कि उन्होंने क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। देश और विदेश के हर कोने में लाखों भारतीय इस जीत का जश्न मना रहे हैं। आप रोल मॉडल बन गई हैं। युवा पीढ़ी, खासकर लड़कियां, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगी।

♥♥ टीम इंडिया की विश्व कप जीत पर हर भारतीय को बेहद गर्व है। महिला क्रिकेट टीम के साथ बातचीत करना वाकई बहुत अच्छा रहा। ♥♥

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

पीएम मोदी से बातचीत के दौरान कप्तान हरमनप्रीत ने कहा आपने (प्रधानमंत्री) कहा था कि जब भी आपको अगला अवसर मिले तो अपना बेस्ट दें। आज हम फाइनल जीत कर आए हैं तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। उप कप्तान स्मृति मंधाना ने भी बातचीत में वर्ष 2017 की मुलाकात और उससे मिले लाभ का जिक्र किया।

फिट इंडिया को दें बढ़ावा

मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से कहा कि आपके हाथ में सफलता की एक बहुत बड़ी ताकत है। ऐसे में मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत मोटिवेट कर सकते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को अपने स्कूलों में जाकर वहां के छात्रों को प्रेरित करने की सलाह देते हुए कहा कि जिस स्कूल से आप पढ़ कर निकली हैं, एक दिन उसमें बिताएं। बच्चों से बातें करें, वो आपको ढेर सारे सवाल पूछेंगे। मैं समझता हूं कि वो स्कूल और बच्चे जीवन भर आपको याद रखेंगे। फिर आप तीन स्कूल सिलेक्ट कीजिए। साल में जब भी मौका मिले, वहां जाईये। देश में मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में फिट इंडिया ही उसका उपाय है। मैं हमेशा कहता हूं कि खाने का तेल 10% कम कीजिए। ये चीजें जब आपके मुंह से लोग सुनते हैं तो बहुत फायदा होता है। बेटियों से फिट इंडिया का आग्रह करें। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा लाभ होगा। उसमें अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप लोगों को करना चाहिए।

बहुत मैटर करती है टीम स्पिरिट

महिला खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने टीम स्पिरिट की बात की। खेल में टीम स्पिरिट बहुत मैटर करता है। टीम स्पिरिट सिर्फ मैदान में ही हो ऐसा नहीं है। अब 24 घंटे एक साथ रहते हैं तो एक प्रकार कि बॉन्डिंग बन जाती है। हर एक को एक-दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता होता है। तभी वीकनेस को कवर करने और स्ट्रेंथ को सामने लाने एवं बढ़ाने की कोशिश होती है। ■

पीएम मोदी से जब कहा- आप बहुत ग्लो करते हो सर...

महिला क्रिकेट खिलाड़ी हरलीन कौर देओल ने बातचीत में कहा कि सर, मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना था। आप बहुत ग्लो करते हो सर। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि मैंने इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। जिस पर खिलाड़ी ने कहा कि सर, ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आपके लिए। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि ये तो है ही है जी। यह बहुत बड़ी ताकत होती है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गया है। यह लंबा समय होता है, उसके बाद भी जब इतने आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक प्रभाव तो रहता है।



सीमा से ही नहीं, संस्कृति से भी हैं जुड़े भारत-भूटान

हिमालय की गोद में बसे भूटान और भारत के बीच का रिश्ता केवल सीमा से नहीं, बल्कि संस्कृति और संवेदनाओं से भी जुड़ा है। दशकों से यह संबंध विश्वास, सहयोग और साझी समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा है। इन्हीं संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 नवंबर को भूटान की यात्रा पर रहे। इस दौरान दोनों देशों के बीच हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय और समझौते...

भारत और भूटान के बीच मैत्री और सहयोग का एक अटूट रिश्ता है जो गहरे आपसी विश्वास, समझ और सद्भावना पर आधारित है। दोनों देशों के बीच यह साझेदारी भारत की 'पड़ोसी प्रथम' की नीति का एक प्रमुख स्तंभ और पड़ोसी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का एक आदर्श भी है। यही वजह है कि भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय यात्रा पर भूटान गए। यात्रा के दौरान पीएम मोदी थिम्पू में चतुर्थ डुक ग्यालपो की 70वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी भाग लिया। भारत में पुरखों की प्रेरणा है 'वसुधैव कुटुम्बकम्' यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। ऐसे में 'सर्वे भवन्तु

सुखिनः' मंत्र के माध्यम से सभी के सुखी होने की प्रार्थना दोहराई।

पीएम मोदी ने भूटान के चतुर्थ नरेश को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन को ज्ञान, सादगी, साहस और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा का संगम बताते हुए कहा कि इन्होंने 16 वर्ष की अल्पायु में ही बहुत बड़ा दायित्व ग्रहण किया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व से देश को आगे बढ़ाया। अपने 34 वर्षों के शासनकाल में भूटान की विरासत और विकास दोनों को एक साथ लेकर चले। लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति को बढ़ावा देने तक निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने यह बताया कि राष्ट्र निर्माण केवल सकल घरेलू उत्पाद से नहीं बल्कि मानवता की भलाई से होता है। भारत और भूटान के बीच मैत्री को मजबूत करने में भूटान के चतुर्थ



घोषणाएं...

1,200
मेगावाट

पुनात्सांगछु-I जलविद्युत परियोजना की मुख्य बांध संरचना पर फिर से काम शुरू करने पर सहमति बनी।

- वाराणसी में भूटानी मंदिर/बौद्ध मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि का अनुदान।
- गेलेफू के पार हतिसार में आव्रजन जांच चौकी स्थापित करने का निर्णय।
- भूटान को 4,000 करोड़ रुपये की ऋण सहायता।

दोनों देशों के बीच हुए समझौते

- दोनों देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्वास्थ्य सेवा।
- नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य और विकित्सा क्षेत्र।
- पीईएमए सचिवालय और भारत सरकार के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान के बीच संबंध निर्माण।

दिल्ली की घटना के बाद भूटान की एकजुटता के लिए आभार

पीएम मोदी ने कहा आज का दिन भूटान के शाही परिवार और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए अहम है लेकिन वह (पीएम मोदी) भारी मन से यहां पहुंचे हैं, क्योंकि एक दिन पहले दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी को बहुत व्यथित कर दिया है। घटना की जांच में शामिल सभी एजेंसियों के साथ रात भर निरंतर संपर्क में था। भारत की एजेंसियां पूरे षड्यंत्र की तह तक जाएंगी और जिन षड्यंत्रकारियों का हाथ है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली की घटना के बाद भूटान की एकजुटता की भावना के लिए आभार व्यक्त किया।

♥ महामहिम चतुर्थ नरेश के 70वें जन्मदिन के कार्यक्रम में, भूटान के लोगों ने एक विशेष प्रार्थना में दिल्ली में हुए विस्फोट पर भारत के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। मैं इस भाव को कभी नहीं भूलूंगा। ♥

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

नरेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने जो नींव रखी उस पर दोनों देशों की मित्रता निरंतर फल-फूल रही है।

भारत-भूटान जलविद्युत सहयोग की नींव चतुर्थ नरेश के नेतृत्व में रखी गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी इस दूरदर्शी नींव ने भूटान को दुनिया का पहला कार्बन-निगेटिव देश बनने में सक्षम बनाया है जो असाधारण उपलब्धि है। प्रति व्यक्ति नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भूटान विश्व के सर्वोच्च देशों में से एक है। वर्तमान में अपनी 100 प्रतिशत बिजली का उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से करता है। इस क्षमता का और विस्तार करते हुए 1,000 मेगावाट से अधिक की एक नई जलविद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया जिससे भूटान की जलविद्युत क्षमता में 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी। पीएम मोदी ने कहा यह साझेदारी केवल जलविद्युत तक ही सीमित नहीं है। भारत और भूटान अब सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक साथ बड़े कदम उठा रहे हैं।

दोनों देश कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी ध्यान दे रहे हैं। इसी कड़ी में

भारत और भूटान सरकार के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत निर्मित 1020 मेगावाट पुनात्सांगछु-II जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन

गेलेफु और समत्से शहरों को भारत के विशाल रेल नेटवर्क से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। यह परियोजना पूरी होने पर भूटान के उद्योगों और किसानों की भारत के विशाल बाजार तक पहुंच और आसान हो जाएगी। भारत जल्द ही आगंतुकों और निवेशकों की सुविधा के लिए गेलेफु के पास आव्रजन चौकी भी स्थापित करेगा। भारत ने पिछले वर्ष भूटान की पंचवर्षीय योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपये की सहायता पैकेज की घोषणा की थी। इस निधि का उपयोग सड़कों से लेकर कृषि, वित्तपोषण से लेकर स्वास्थ्य सेवा व अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। इससे भूटान के नागरिकों का जीवन सुगम होगा। ■



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी स्थिरता और आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा

वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन और निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी है। इससे निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस निर्णय से दुनिया में 'मेड इन इंडिया' की गूंज और प्रभावी होगी। साथ ही चार महत्वपूर्ण खनिजों ग्रेफाइट, सिजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम की रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत बनाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने दी है मंजूरी...

निर्णय : 25,060 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत के निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी।

प्रभाव : यह मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित खाका उपलब्ध कराएगा। मिशन, कई योजनाओं से परिणाम-आधारित और अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है। यह वैश्विक व्यापार चुनौतियों और उभरती निर्यातक जरूरतों को पूरा कर सकता है। इस प्रमुख पहल की घोषणा इस वर्ष के बजट में भारत के निर्यात को विशेष रूप से एमएसएमई के पहली बार के निर्यातकों और श्रम क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए की गई थी।

निर्णय : निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई) शुरू करने को मंजूरी।

प्रभाव : इसके तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सकेगा। ताकि पात्र निर्यातकों, जिनमें एमएसएमई भी शामिल हैं, उसे 20,000 करोड़ रु. तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

- इस योजना से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और नए व उभरते बाजारों में विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- इससे रोजगार को बढ़ावा और आत्मनिर्भर भारत की ओर देश की यात्रा को और मजबूती मिलेगी।

निर्णय : हरित ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण ग्रेफाइट, सिजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम खनिजों की रॉयल्टी दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी।

प्रभाव : इस निर्णय से सिजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम युक्त खनिज ब्लॉकों की नीलामी को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल इन खनिजों का उपयोग किया जा सकेगा बल्कि उनके साथ पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम, टंगस्टन, आर्आईईएस, नाइओबियम आदि का भी उपयोग किया जा सकेगा। इन खनिजों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि से आयात और आपूर्ति श्रृंखला की खामियों में कमी आएगी। साथ ही देश में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ग्रेफाइट, सिजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम हाई-टेक एप्लीकेशन और ऊर्जा ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण खनिज हैं।

- ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरी का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह मुख्य रूप से एनोड सामग्री के रूप में काम आता है।
- जिरकोनियम का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। इसमें परमाणु ऊर्जा, एयरोस्पेस, स्वास्थ्य देखभाल और विनिर्माण शामिल हैं।
- सिजियम का उपयोग मुख्य रूप से उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में किया जाता है।
- रुबिडियम का उपयोग फाइबर ऑप्टिक्स, दूरसंचार प्रणाली, नाइट विजन उपकरणों आदि में उपयोग किए जाने वाले विशेष चश्मे बनाने में किया जाता है।



कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस ब्रीफिंग देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



Narendra Modi
@narendramodi

This Cabinet decision will boost sustainability and self-reliance. It will strengthen supply chains and create job opportunities as well.

pib.gov.in/PressReleasePa...



रक्षा मंत्री सर्वार्थदायक / RMO India
@DefenceMinIndia

Technology is not only a tool but a culture. It is a way of doing things better, faster and more intelligently. It is about ensuring that data moves faster than doubt, that decision-making is informed by evidence and that the soldier, the scientist and the civil servant all work in synergy through shared platforms: Raksha Mantri Shri @rajnathsingh



Amit Shah
@AmitShah

दो लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाया जायेगा।



Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

On this #WorldScienceDay, let's celebrate the power of knowledge and innovation that shape a sustainable future. May science continue to guide us toward solutions for our planet's greatest challenges—advancing progress, equity, and hope for generations to come. Happy World Science Day!



Shivraj Singh Chouhan
@ChouhanShivraj

घटिया बीज एक समस्या है, इसे बेचने वालों को रोकने के लिए हम सीड एक्ट ला रहे हैं...



Manohar Lal
@mankhustar

Urban Invest Window (UIWin) सतत, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहरों के रोडमैप की दृष्टिकोण से एक गेमचेंजर साबित होगा...

सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं बिरसा मुंडा

समरकण्ड के 25 वीं वार्षिक संविधान और समृद्धि के ड्रेक-याका त्योहार को

बिरसा मुंडा का जन्म 1874 में छत्तीसगढ़ के बिरसा में हुआ था। उन्होंने 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1929 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया।

मुंडा समाज के नेता बिरसा मुंडा का जन्म 1874 में छत्तीसगढ़ के बिरसा में हुआ था। उन्होंने 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1929 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया।

मुंडा समाज के नेता बिरसा मुंडा का जन्म 1874 में छत्तीसगढ़ के बिरसा में हुआ था। उन्होंने 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1929 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया।

मुंडा समाज के नेता बिरसा मुंडा का जन्म 1874 में छत्तीसगढ़ के बिरसा में हुआ था। उन्होंने 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1929 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया।

लखनऊ में बनी ब्रह्मास मिसाइल खरीदने में इंडोनेशिया की रुचि : राजनाथ सिंह

बोले, इस मिसाइल का निर्माण शहद के लिए मोटव की बात

लखनऊ, 15 फरवरी (एनआई) : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ की यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जकार्ता के साथ एक बैठक में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री से मिली।

इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ की यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री से मिली।

इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ की यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री से मिली।

इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ की यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री से मिली।

'बुलेट ट्रेन परियोजना के अभियंता अनुभवों का करें दस्तावेजीकरण'

पीएम मोदी-प्रोजेक्ट के अनुभवों को 'बुलेट ट्रेन' की तरह करें दर्ज

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन परियोजना के अभियंता अनुभवों का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक आदेश जारी किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन परियोजना के अभियंता अनुभवों का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक आदेश जारी किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन परियोजना के अभियंता अनुभवों का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक आदेश जारी किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन परियोजना के अभियंता अनुभवों का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक आदेश जारी किया।

दुनिया में बढ़ेगी मेड इन इंडिया की गूंज: PM निर्यातकों ने कहा, EPM और क्रेडिट गारंटी स्कीम से एक्सपोर्ट बढ़ाने में मिलेगी मदद

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बढ़ेगी मेड इन इंडिया की गूंज का दावा किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बढ़ेगी मेड इन इंडिया की गूंज का दावा किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बढ़ेगी मेड इन इंडिया की गूंज का दावा किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बढ़ेगी मेड इन इंडिया की गूंज का दावा किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बढ़ेगी मेड इन इंडिया की गूंज का दावा किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बढ़ेगी मेड इन इंडिया की गूंज का दावा किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बढ़ेगी मेड इन इंडिया की गूंज का दावा किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बढ़ेगी मेड इन इंडिया की गूंज का दावा किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बढ़ेगी मेड इन इंडिया की गूंज का दावा किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बढ़ेगी मेड इन इंडिया की गूंज का दावा किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बढ़ेगी मेड इन इंडिया की गूंज का दावा किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बढ़ेगी मेड इन इंडिया की गूंज का दावा किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बढ़ेगी मेड इन इंडिया की गूंज का दावा किया।

टीबी के खिलाफ लड़ाई में मिली बड़ी कामयाबी: मोदी

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में मिली बड़ी कामयाबी का दावा किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में मिली बड़ी कामयाबी का दावा किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में मिली बड़ी कामयाबी का दावा किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में मिली बड़ी कामयाबी का दावा किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में मिली बड़ी कामयाबी का दावा किया।

नई दिल्ली, 15 फरवरी (एनआई) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में मिली बड़ी कामयाबी का दावा किया।

6 दिसंबर
2025

70^{वां}

महापरिनिर्वाण दिवस

सामाजिक न्याय के प्रणेता, भारतीय संविधान के शिल्पकार और भारत रत्न से सम्मानित डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन में बना भारतीय संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का मूल मंत्र है। संविधान ने हर भारतीय के सपने को अधिकारों और अवसरों में बदलने का मार्ग दिखाया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण हुआ जिन्होंने ऐसा संविधान दिया जो हमारी गरिमा और समानता सुनिश्चित करता है। इसके लिए भारत की पीढ़ियां डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति रहेगी अभारी... बाबा साहेब को राष्ट्र का नमन...



दिल्ली में डॉ. अंबेडकर
अंतरराष्ट्रीय केंद्र



जन्मभूमि मठ में स्मारक



नागपुर, दीक्षा भूमि



मुंबई, चैत्य भूमि



लंदन में शिक्षा भूमि

न्यू इंडिया
समाचार
पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, दिसंबर 1-15, 2025

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर- DL (S)-1/3550/2023-25 डब्ल्यूपीपी संख्या- U (S)-98/2023-25, posting at BPC, Market Road, New Delhi - 110001 on 26-30 advance Fortnightly (प्रकाशन तिथि- 18 नवंबर 2025, कुल पृष्ठ-52)

प्रधान संपादक:
धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रक:
कंचन प्रसाद,
महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो,
सूचना भवन, द्वितीय तल,
नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि.,
बी-278, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1,
नई दिल्ली-110020